राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 36 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,06 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

41 साल बाद हॉकी में जीता ओलंपिक पदक

जर्मनी को 5-4 से मात देकर कांस्य पर जमाया कब्जा, भारत ने आखिरी बार 1980 में जीता था सोना

जीत के शिल्पकार

2 गोल- 17 वें और 34 वें मिनट में

1 गोल- 13 वें मिनट में

1 गोल- 27 वें मिनट में

1 गोल- 31 वें मिनट में

9 गोल रोके और अंतिम 6 सेकेंड पेनल्टी कॉर्नर रोका

रवि दहिया ने रेसलिंग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, सोना हाथ से फिसला

नई दिल्ली । भारत के स्टार पुरुष रेसलर रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलिंपिग 2020 में मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में अपने विरोधी रुस के पहलवान जावुर उगुवे से हार गए और उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया। रवि दहिया को इस मैच में 4-7 से हार मिली और उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो ओलिंपिक में ये भारत का दूसरा सिल्वर मेडल है। रवि से पहले मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था।

फाइनल में रवि कुमार दहिया का प्रदर्शन- इस फाइनल मैच की शुरुआत में ही रूस के पहलवान ने रवि पर अटैक करते हुए 2-0 की बढ़त बना ली, लेकिन फिर रवि ने वापसी की और 2-2 की बराबरी पर आ गए। इसके बाद रूस के पहलवान ने टेक डाउन के साथ दो अंक और अर्जित कर ली और 4-2 की बढ़त बना ली। इसके बाद रवि विरोधी पहलवान के सामने थोड़े ढ़ीले नजर आए और जावुर ने बढ़त 7-2 की कर ली। आखिरी में रवि ने जोर लगाते हुए 2 अंक जरूर हासिल किए, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं थे और उन्होंने मैच गंवा दिए।

टोक्यो ओलिंपिक 2020 में रवि दहिया का सफर- रवि दहिया का सफर इस ओलिंपिक में कमाल का रहा और उन्होंने सबसे पहले राउंड 16 में कोलंबिया के पहलवान को 13-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बुल्गारिया के पहलवान को 14-4 के बड़े अंतर से चित किया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के पहलवान से कड़ी टक्कर मिली साथ ही साथ कजाक पहलवान ने उन्हें दांतो से भी काटा, इसके बावजूद वो मैदान पर डटे रहे और आखिरकार जीत उनकी झोली में आई। इस मुकाबले में रवि कुमार ने जीत के अंतर को 5-9 से कम कर दिया था और फिर आखिरी मिनटों में ये मुकाबला रवि ने कजाक पहलवान को नीचे गिराते हुए बाय फॉल के आधार पर जीता था।

रवि कुमार दारिया ओलिंपिक में भारत की तरफ से फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले दूसरे रेसलर थे। इससे पहले सुशील कुमार ने ये कमाल साल 2012 लंदन ओलिंपिक में किया था और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था।

सुशील कुमार ने इससे पहले साल 2008 बीजिंग ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब रवि भारत के लिए ओलिंपिग में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे रेसलर बन गए हैं, लेकिन 57 किलो भारवर्ग में वो देश के लिए सिल्वर जीतने वाले पहले रेसलर बन गए।

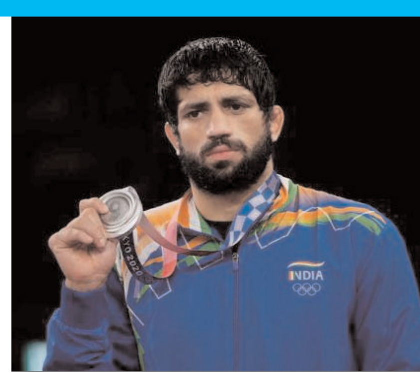

कृष्ण जन्मभूमि के लिए माहौल बनाएगी विहिप

नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण का कार्य अब तेजी चल रहा है और 2023 के अंत तक मंदिर का गर्भगृह तैयार होकर रामलला को विराजमान करने की तैयारी है। राम जन्मभूमि के बाद विश्व हिंदू परिषद अब कृष्ण जन्मभूमि मामले को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, विहिप इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर देशभर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा, जबकि कार्यक्रमों का या प्रारूप होगा, इसको लेकर योजना तैयार की जा रही है। विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक, जन्माष्टमी के दिन विहिप अपना स्थापना दिवस मनाती है।

हनी सिंह की पत्नी शालिनी ने मांगा 10 करोड़ मुआवजा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बॉलीवुड सिंगर और एटर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की डिमांड की है। यह आरोप प्रोटेशन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एट के तहत लगा है। शालिनी का कहना है कि उनके साथ किसी जानवर की तरह बर्ताव किया गया और बदतमीजी भी की गई।

पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा- अपनी याचिका की कॉपी केंद्र को दें, 10 अगस्त को फिर सुनवाई

नई दिल्ली । पेगासस जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। इस मामले में विभिन्न लोगों और संस्थाओं ने कई याचिकाएं दायर की है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एनराम और शशिकुमार, सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और वकील एमएल शर्मा ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दें। मंगलवार (10 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा।

पेगासस मामले की आज की सुनवाई के दौरान एन.राम और अन्य के लिए वरिष्ठ सलाहकार कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस एक दुष्ट तकनीक है, जो हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह हमारे गणतंत्र की निजता, गरिमा और मूल्यों पर हमला है। CJI का कहना है कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में पेगासस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान एन.राम और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल

सिब्बल का कहना है कि यह स्पाइवेयर केवल सरकारी एजेंसियों को बेचा जाता है और निजी संस्थाओं को नहीं बेचा जा सकता है। एनएसओ प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शामिल है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल का तर्क है कि पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, शिक्षाविद सभी स्पाइवेयर द्वारा लक्षित हैं और सरकार को जवाब देना है कि इसे किसने खरीदा ? हार्डवेयर कहां रखा गया था? सरकार ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की? इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को नोटिस जारी करें।

पेगासस जासूसी केस में शिक्षाविद् जगदीप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा है कि वर्तमान मामले की भयावहता बहुत बड़ी है और कृपया मामले की स्वतंत्र जांच पर विचार करें। उन्होंने कहा कि यह सर्वोच्च स्तर का नौकरशाह होना चाहिए, जो इसका जवाब कैबिनेट सचिव को देता है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तर ने कहा कि नागरिकों की गोपनीयता और व्यक्तिगत गोपनीयता पर विचार किया जाना चाहिए। पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन.राम व शशि कुमार द्वारा दी गई याचिकाएं भी शामिल हैं। पेगासस मामले की जांच को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित लोगों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी की खबरों से जुड़ी नौ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

क्या है मामला - गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी साफ्टवेयर के जरिए भारत के दो केन्द्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं और एक न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर खास लोगों की निगरानी संबंधी आरोपों को खारिज किया है। सरकार ने कहा कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है या इससे जुड़ी कोई सच्चाई नहीं है।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने एक खबर में दावा किया कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिये जासूसी के संभावित निशाने वाली सूची में 300 भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल थे।एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि पत्रकारों और अन्य के सर्विलांस की जांच कराने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया जाए।गिल्ड ने अपनी अर्जी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे भी याचिकाकर्ता हैं, में कहा है कि उसके सदस्य और सभी पत्रकारों का काम है कि वे सूचना और स्पष्टीकरण मांग कर और राज्य की कामयाबी और नाकामियों का लगातार विश्लेषण कर सरकार के सभी अंगों को जवाबदेह बनाएं।

पीडीपी ने निकाला विरोध मार्च, भाजपा ने फहराया तिरंगा

श्रीनगर, (एजेंसी)। जमू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी फैसले के गुरुवार को दो साल पूरे हो गए। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और स्थिति शांतिपूर्ण है। वहीं भाजपा ने तिरंगा रैलियां निकालकर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रध्वज फहरा कर जश्न मनाया। पीडीपी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में मार्च निकाला।

जमू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) की एक बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अदुल्ला के आवास पर हुई। बैठक में गठबंधन के उपाध्यक्ष और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुती, उसके प्रवक्ता और माकपा नेता एम वाई तारिगामी तथा आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफर शाह शामिल हुए। पीएजीडी जमू कश्मीर में मुयधारा के विभिन्न दलों का गठबंधन है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली जगह-जगह रैलियां- श्रीनगर में काली पट्टी बांधे पीडीपी के दर्जनों नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुयालय से एक विरोध मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुती ने किया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह रैलियां निकाली और तीरंगा फहराया। अनंतनाग जिले के खानाबल से भाजपा की नगर निगम पार्षद रोमासिया रफीक ने खानाबल में डिग्री कॉलेज के पास राष्ट्रध्वज फहरा कर कश्मीर घाटी में पार्टी के समारोहों की शुरूआत की।

जामिया मस्जिद के पास धमाका

श्रीनगर में जामिया मस्जिद के पास गुरुवार को एक धमाका हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि यह कम तीव्रता वाला आईईडी लास्ट था, जिसके बाद आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने और फायरिंग करने की भी सूचना है। हालांकि इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पीएम मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को लिया आड़े हाथ, इन सभी ने किया उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वाराणसी, कुशीनगर, झांसी, सुल्तानपुर, सहारनपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक-एक लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस कार्यक्रम से जुड़े।

प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद के बाद राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसका सपना देखने वाले तो बहुत से लोग आए और गए लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा की उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रिम

भूमिका निभा सकता है। किसी ने वंशवाद, किसी ने परिवार के लिए और किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थवश यूपी को इस्तेमाल किया। अपने स्वार्थ में डूबे इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को आर्थिक समृद्धि से जोड़ा ही नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। अब उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकल आया है। उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, यह विश्वास हाल के वर्षों में बना है।

पांच अगस्त के महत्व को किया रेखांकित- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच अगस्त की तारीख के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दो वर्ष पहले इसी तारीख को संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार और सुविधाओं में भागीदार बनाया गया था। बीते वर्ष इसी तारीख को कोटि-कोटि भारतीयों ने सैकड़ों वर्ष बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की ओर कदम बढ़ाया था। आज ओलंपिक में हमारे युवाओं ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। आज ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण के लिए यह पुण्य आयोजन हो रहा है। ऐसे समय में जब देश के युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और गोल पर गोल दाग रहे हैं, वही हमारे देश में कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में लगे हैं। देश कैसे बदल रहा है, क्या हासिल कर रहा है, इससे इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। वह देश की भावना को आहत करने में जुटे हैं, संसद की कार्यवाही में बाधा डालकर जन भावना का निरंतर अपमान कर रहे हैं। जब देश का हर नागरिक कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जी-जान से जुटा है तो यह लोग देशभक्ति के काम को रोकने की स्पर्धा में लगे हैं। देश की जनता ऐसी देश विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकती। उनके मंसूबों को नाकाम कर देश हर कठिनाई से पार पाकर आगे बढ़ रहा है। जो अपने पद के लिए परेशान हैं, वे भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीतकर दुनिया पर छा रहा है।

कठिन परिस्थितियों में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां- पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की कठिन परिस्थितियों में भी देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत 50 करोड़ टीके लगाने की दहलीज पर खड़ा है। जुलाई में जीएसटी संग्रह 1.16 लाख करोड़ रुपये हुआ है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में ढाई लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निर्यात हुआ है। कृषि निर्यात में भारत पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है। देश का पहला मेक इन इंडिया विमान वाहक पोत विक्रांत समुद्र में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को चुनौती देते हुए लद्दाख में सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण हुआ है। डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाइयां देने वाला ई रुपी लांच किया गया है।

राज्यसभा में मंत्रियों के आधिकारिक कागजात नहीं रखने पर पी चिदंबरम ने आपत्ति जताई

नई दिल्ली । राज्य सभा में मंत्रियों के आधिकारिक कागजात नहीं रखने का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मुद्दा उठाया है। गुरुवार को रायसभा में संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन को उनके छह मंत्री सहयोगियों की ओर से आधिकारिक कागजात रखने के लिए भेजा गया। जिस पर चिदंबरम ने आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कागजात रखने के लिए मंत्रियों के रायसभा में मौजूद नहीं होने की बात से आपत्ति जताई।

पी चिदंबरम ने कहा- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को मंत्रियों की सदन में आधिकारिक कागजों को नहीं रखने के मुद्दे को उठाते हुए कहा, हम समझ सकते हैं, कि संसदीय मंत्री कभी-कभी अपने सहयोगियों की ओर से एक पेपर सदन पटल पर रखते हैं, जो किसी कारण से सदन में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं। लेकिन हर दिन हम देखते हैं कि संसदीय मामलों के मंत्री आधा दर्जन मंत्रियों के लिए कागजात लाते हैं। पी चिदंबरम ने ऐसे मंत्रियों से सवाल करते हुए कहा कि वे आधा दर्जन मंत्री रायसभा का सम्मान नहीं करते हैं। हर दिन ऐसा हो रहा है, आप यह कैसे कर सकते हैं।

कोरोना काल में शुरू हुई यह प्रथा- मंत्रियों द्वारा आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कागजात रखने के लिए मंत्रियों के रायसभा में मौजूद नहीं होने की यह प्रथा कोरोना काल से पिछले सत्र में शुरू हुई, जब सदन का कामकाज बंद कर दिया गया और सांसदों को शारीरिक दूरी की अनुमति देने के लिए लॉबी के साथ-साथ लोकसभा में भी बैठाया गया। इस मुद्दे पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि मामला बुधवार को भी उठाया गया था और सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री को कोविड 19 की स्थिति के कारण अन्य मंत्रियों के नामों के खिलाफ उल्लेखित कागजात रखने की अनुमति दी गई है। फिलहाल रायसभा में सभी सदस्य और मंत्री अब सदन में मौजूद रहते हैं।कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बुधवार को सदन में कहा था, नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कागजात संबंधित मंत्री द्वारा रखे जाएंगे। केवल जब विशिष्ट अनुमति ली जाती है, तो कोई अन्य सहयोगी या संसदीय कार्य मंत्री कागजात रखेंगे। साथ ही जो मंत्री सदन में मौजूद हैं उन्हें कागज न रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।झ

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान में विपक्षी दलों की मांग, सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील करने का दिया जाए अधिकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से आग्रह किया कि देश की सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी नागरिकों को उसी प्रकार अपील करने का अधिकार दिया जाए जैसे एक प्रस्तावित कानून के जरिये भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को दिया गया है। जून में नेशनल असेंबली में एक कानून पारित किया गया था जिसके जरिए जाधव को अपील का अधिकार दिया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए लाया गया था। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से कहा है कि देश की सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी नागरिकों को इसी तरह अपील करने का अधिकार दिया जाए।

बाइडन के इमरान खान को फोन नहीं करने पर चिढ़ा पाकिस्तान, कहा- विकल?प मौजूद हैं

इस्लामाबाद। 20 जनवरी, 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति के पर काबिज होने के बाद से जो बाइडेनने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के कई नेताओं को फोन किया है। हालांकि, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के पीएम से संपर्क नहीं किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन के इंतजार में हैं। इमरान ने जनवरी में पद संभालने के बाद डेमोक्रेट नेता को बधाई दी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद युसूफ ने एक साक्षात्कार में पाकिस्तान का ये दर्द साफ झलकता है। युसूफ ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतने महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं की है, जबकि अफगानिस?तान के लिहाज से हमारा देश महत?वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें हर बार कहा जाता है कि फोन कॉल आएगा। ये कोई तकनीकी समस्या है या कुछ और। सच कहूं तो अब लोगों को विश्वास नहीं है।

50 तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण किया: अधिकारी

काबुल। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान में बेरोकटोक हिंसा के बीच, कम से कम 50 तालिबान आतंकवादियों ने देश के उत्तरी प्रांत जज्जान में आत्मसमर्पण कर दिया। मंत्रालय के उप प्रवक्ता फवाद अमन ने ट्विटर पर लिखा, 50 तालिबान ने अपने हथियारों और गोला-बारूद के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की तस्वीरें और फुटेज के साथ विवरण जल्द ही मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। तालिबान आतंकवादी समूह ने अब तक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रांत हाल के दिनों में भारी संघर्ष और लड़ाई का दृश्य रहा है क्योंकि आतंकवादियों ने शहर पर कब्जा करने के प्रयास में प्रांतीय राजधानी शिबरघन को घेर लिया था।

अमेरिका ने अफगान रक्षा मंत्री पर हमले की निंदा की

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगान रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर लक्षित हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है, जिसका दावा बाद में तालिबान ने किया था। बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए, विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हालांकि मंत्री मौजूद नहीं थे, रिपोटरे से संकेत मिलता है कि हमले में आठ लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। तालिबान ने इस शर्मनाक कृत्य की जिम्मेदारी ली है। तालिबान को इस जारी हिंसा को रोकना चाहिए। उन्हें इसे रोकना चाहिए। प्राइस ने दोहराया कि दशकों से चली आ रही हिंसा के इस चक्र को खत्म करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा, यह हिंसा का एक चक्र है जो बहुत लंबे समय तक चला है, और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम इसे खत्म करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। मंगलवार शाम को, आतंकवादियों के एक समूह ने रक्षा मंत्री के घर के बगल में एक कार बम विस्फोट किया, जिसमें पांच घंटे की मुठभेड़ हुई और चार हमलावरों और आठ नागरिकों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। कुछ घंटे बाद तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि तालिबान आतंकवादी और सरकारी बलों के खिलाफ भारी लड़ाई जारी है और वे 1 मई को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से जमीन हासिल कर रहे हैं। सोमवार को संसद में अपनी टिप्पणी में, अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने बिगड़ती स्थिति के लिए अमेरिकी सैनिकों कीवापसी को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेना को इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान में अपने मिशन को समाप्त करने का आदेश दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 95 प्रतिशत से अधिक निकासी पूरी हो चुकी है।

रॉकेट हमले के बाद लेबनान और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम का आग्रह

बेरुत। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूनिफिल) ने बेरूत और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम का आग्रह किया है और रॉकेट दागे जाने के बाद आगे बढ़ने से बचने के लिए अधिकतम संयम बरतने को कहा है। यूनिफिल के रणनीतिक उप प्रमुख कैंडिस अर्डील संचार और सार्वजनिक सूचना,बुधवार को एक बयान में कहा,यूनिफिल हमारे संपर्क और समन्वय चैनलों के माध्यम से पार्टियों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम लेबनानी सशस्त्र बलों के साथ काम कर रहे हैं ताकि जमीन पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और ब्लू लाइन के साथ सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। समाचार एजेंसी ने अर्डील के हवाले से कहा, स्थिरता तुरंत बहाल करना अनिवार्य है ताकि यूनिफिल अपनी जांच शुरू कर सके। बुधवार को दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इस्राइल पर तीन रॉकेट दागे जाने से चार इस्राइली घायल हो गए थे।

भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में होगी अफगानिस्तान पर चर्चा

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)की बैठक मे अफगानिस्तान में बदतर होती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान पर खुली यूएनएससी चर्चा आयोजित करने का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार के बात करने के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन सत्र बुलाने पर चर्चा की थी।'

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने बुधवार रात ट्वीट किया, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार, छह अगस्त को अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करने और उसका जायजा लेने के लिए बैठक करेगा।' अतमार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तालिबान की हिंसा एवं अत्याचार के कारण अफगानिस्तान में सामने आ रही त्रासदी रोकने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। अतमार ने ट्वीट किया, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा

अध्यक्ष की अग्रणी भूमिका की सराहना करता हूं।' अमेरिका और नाटो सैनिकों का युद्धग्रस्त देश से वापस जाने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही तालिबान और अफगानिस्तान के सरकारी बलों के बीच लड़ाई पिछले कुछ महीनों में तेज हो गई है।' इस महीने के लिए सोमवार को अपनाए गए परिषद की कार्य सूची के अनुसार अफगानिस्तान पर बैठक इस दौरान निर्धारित नहीं थी।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाताओं को विवरण उपलब्ध कराते हुए तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान में स्थिति पर और युद्धग्रस्त देश में तनाव और बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद क्या कर सकता है इसपर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान पर 'संभवतः सुरक्षा परिषद इस पहलू पर जल्द से जल्द गौर करेगी'। यह महत्त्वपूर्ण है कि परिषद की भारत की अध्यक्षता के पहले हफ्ते के भीतर अफगानिस्तान पर खुली चर्चा हो रही है जो अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति पर फौरन चर्चा की जरूरत को दर्शाती है।

तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है- और 'हमने हाल के दिनों में देखा है कि हिंसा केवल बढ़ रही है।' उन्होंने कहा कि जहां तक भारत की बात है उसने साफ तौर पर बता दिया है कि, ÷हम स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, भारत ने हर उस अवसर का समर्थन किया है जो अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता ला सकता है।' तिरुमूर्ति ने कहा, 'हम आश्वस्त हैं कि ... हमें हिंसा और लक्षित हमलों के सवालों का हल करना चाहिए और ये बहुत गंभीर चिंताएं हैं और सभी प्रकार की हिंसा समाप्त होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के साथ संबंध भी तोड़े जाने चाहिए। हम अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकवादी ठिकानों को बसते हुए नहीं देखना चाहते। और इसका भारत पर सीधा असर होगा।

इमरान खान ने अब्दुल कयूम नियाजी को पीओके का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम सलाह-मशविरे के बाद बुधवार को अपनी पार्टी के विधायक अब्दुल कयूम नियाजी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया। नियाजी ने हाल ही में अब्बासपुर-पुंछ इलाके से चुनाव जीता है। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को 53 सदस्यीय सदन में 32 सीटें मिली हैं। खान की पार्टी पीओके में पहली बार सरकार बना रही है। भारत ने पीओके में हाल में हुए चुनावों को खारिज करते हुए कहा कि ''दिखावे का यह चुनाव'' और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा ''अपना अवैध कब्जा छुपाने'' का प्रयास है और वह (भारत) इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराता है।

पीओके के चुनाव पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ''भारत की सीमा में पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं बनता है'' और उसे अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन छोड़ देनी चाहिए। बागची ने पिछले सप्ताह कहा, ''पाकिस्तान के अवैध कब्जे में मौजूद भारतीय सीमा में तथा-कथित चुनाव और कुछ नहीं बल्कि अवैध कब्जे और इलाके में उसके द्वारा किए गए बदलावों को छुपाने का पाकिस्तान का तरीका है।'' उन्होंने कहा, ''ऐसी कवायद कभी भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे, मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन और कब्जे वाले इलाके के लोगों को आजादी नहीं देने को, छुपा नहीं सकेगी।''

पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने विस्तृत सलाह मशविरा के बाद नियाजी को पीओके में पीटीआई सरकार का प्रमुख चुना है। उन्होंने लिखा है, ''लंबी चर्चा और सभी सलाह मशविरा पर गौर करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने नवनिर्वाचित विधायक अब्दुल कयूम नियाजी को पीओके के पधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है।

पाकिस्तान में उपद्रवियों की भीड़ ने हिंदू मंदिर पर किया हमला, मूर्तियां तोड़ीं

लाहौर। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला किया, उसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी और मूर्तियों को खंडित किया। पुलिस जब इस भीड़ को रोकने में विफल रही तो हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में भीड़ ने बुधवार को हिंदू मंदिर पर हमला किया। यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है और बताया गया कि कथित तौर पर एक मदरसे की बेअदबी की घटना के बाद कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस वाकये को अंजाम दिया। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते आठ वर्षीय हिंदू बालक ने इलाके के मदरसे के पुस्तकालय में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद भोंग में तनाव व्याप्त हो गया।

इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद डॉ. रमेश कुमार वांकवानी ने बुधवार को, मंदिर पर हमले के वीडियो ट्विटर पर साझा किए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया कि वे ''आगजनी और तोड़फोड़'' को रोकने के लिए जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना को लेकर अनेक ट्वीट किए। इनमें उन्होंने कहा, '' रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला। कल हालात बहुत तनावपूर्ण थे। स्थानीय पुलिस की शर्मनाक लापरवाही। प्रधान न्यायाधीश से

कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।'' रहीम यार खान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) असद सरफराज के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हालात काबू में कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया है। उन्होंने कहा, ''रेंजर्स को बुलाया गया और हिंदू मंदिर के इर्द-गिर्द तैनात किया गया।'' डीपीओ ने बताया कि इलाके में करीब 100 हिंदू परिवार रहते हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है।

इस घटना के संबंध में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ''हमारी पहली प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को बहाल करना और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करना है।'' एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंदिर को बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा, '' हमलावरों के पास डंडे, पत्थर और ईंटे थीं। धार्मिक नारे लगाती भीड़ ने मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर के एक हिस्से को जला दिया गया।'' पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय को कथित तौर पर अपवित्र करने वाले आठ वर्षीय बालक के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज कर पिछले हफ्ते उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वह नाबालिग है इसलिए उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर भोंग के लोगों को इस घटना का बदला लेने के लिए उकसाया गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और बाद में उसने उस पर हमला कर दिया। सरफराज ने कहा, '' हम मंदिर पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार करेंगे।

भारतीय महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, न्याय की आस में दर-दर भटक रही

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

मार्च में अमेरिका आई एक नवविवाहित भारतीय महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और न्याय पाने की आस में कई हफ्तों से दर-दर भटक रही है। बिहार के पटना की रहने वाली महिला ने भारत सरकार, यहां भारतीय दूतवास और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्यिक दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई एक शिकायत में कहा, 'मेरे पति ने बिना किसी वित्तीय सहायता के मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरा यहां कोई आसरा नहीं है। भारत में मेरे माता-पिता ने मेरे ससुर से मदद मांगी है लेकिन वह मेरे पति के पास वापस मुझे भेजने के लिए दहेज मांग रहे हैं।'

अनामिका (परिवर्तित नाम) ने न्याय मांगने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया जिसने उसके पति को एफ-1 छात्र वीजा जारी किया था। उसने फ्रेडी मैक का भी रुख किया है जहां

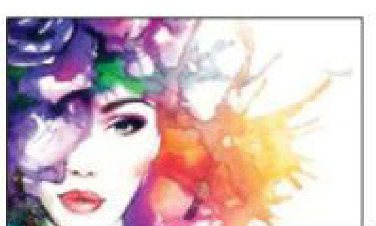

उसका पति अस्थायी रूप से कार्यरत है लेकिन उसे अब तक इस संबंध में कोई राहत नहीं मिली है। उत्पीड़न एवं प्रताड़ना इस स्तर पर पहुंच गई थी कि 15 जन को वाशिंगटन डीसी के वर्जीनिया उपनगर के मैकलेन स्थित उनके अपार्टमेंट में पुलिस को बुलाना पड़ा था। उसने अपनी शिकायत में लिखा, 'पुलिस ने मुझे कैब में बिठाया।' स्थानीय फेयरफेक्स काउंटी पुलिस ने उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की और वह इसे आपराधिक शिकायत के तौर पर देख रहे हैं। उसने पीटीआई-को बताया, 'पुलिस ने उसकी क्रूरता से मुझे बचाया क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में थी।' अनामिका ने उसकी शिकायत में कहा, 'मैं अपने पति के साथ एक मार्च, 2021 को अमेरिका पहुंची थी और उसके साथ वर्जीनिया के मैकलेन में रह रही थी। अमेरिका पहुंच कर, मेरे पति ने मेरे साथ घरेलू हिंसा करनी शुरू कर दी थी और मेरे माता-पिता से दहेज मांगने लगे।÷ वहीं, पति ने आरोपों से इनकार किया है और पीटीआई-को बताया कि उसे फंसाया जा रहा है।

अनामिका का आरोप है कि उसका पति उसपर आरोप लगाता था कि वह गर्भवती होने से बचने के लिए कुछ न कुछ करती है और इसको लेकर वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। 'साउथ एशिया माइनोरिटीज अलायंस फाउंडेशन' ने कहा कि वह अमेरिका में कार्य वीजा पर काम कर भारतीय या दक्षिण एशियाई पेशेवरों से विवाहित 'लड़कियों के उत्पीड़न' के मामलों को विदेश मंत्रालय समेत अमेरिका में अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने की योजना बना रहा है।

मेघन मार्कल के जन्मदिन पर प्रिंस हैरी ने किया विशेष केक ऑर्डर, जानिए कीमत

तोयों (एजेंसी)।

4 अगस्त को मेघन मार्कल के 40वें जन्मदिन पर उनके पति प्रिंस हैरी ने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में पॉसीज एंड शुगर नाम की एक बेकरी से एक विशेष केक ऑर्डर किया। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट है कि मेघन का जन्मदिन उनके सांता बारबरा के 11 मिलियन पाउंड की हवेली में मनाया जाएगा।

पॉसीज न्यूड केक के लिए नेकेड केक के लिए जाना जाता है, जिसमें केक की परतें आइसिंग के नीचे दिखाई देती हैं और इसे ताजे फूलों से भी सजाया जाता है। बेकरी में वनीला बीन, मामाज चॉकलेट, स्ट्राबेरी ब्लिस, कोकोनट ड्रीम और लेमन ड्रॉप जैसे विभिन्न प्रकार के केक बनाए जाते हैं। क्लासिक व्हाइट बटरक्रीम से लेकर मेपल क्रीम चीज, पीनट बटर और चॉकलेट बटरक्रीम तक कई तरह के फ्रॉस्टिंग उपलब्ध हैं।

इतनी है कीमत?

इस बेकरी की वेबसाइट की मूल्य सूची के अनुसार, 30 मेहमानों तक के लिए इस केक की कीमत 225 अमेरिकी डॉलर या लगभग 16,691 रुपये है। बेकरी के मेन्यू में यह सबसे बड़ा केक है। वहीं मेघन के लिए जिस केक को ऑर्डर किया गया है, माना जा रहा है उसकी कीमत कीमत 225 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

ये होंगे गेस्ट

अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और लेबनानी-ब्रिटिश बैरिस्टर अमल क्लूनी मेघन की पार्टी में अतिथि होंगे। बता दें कि हाल ही प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल ने जनवरी 2020 में सीनियर रॉयल्स का पद छोड़ दिया था। दंपति ने मार्च में अपनी सांता बारबरा हवेली खरीदी, जहां वे बेटे-आर्ची और बेटी लिलिबेट के साथ रहते हैं।

अफगानिस्तान में इस साल अब तक 3,60,000 लोग विस्थापन के लिए मजबूर हुए : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष के कारण इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 3,60,000 लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने लश्करगाह में लोगों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जतायी जहां तालिबान के साथ लड़ाई के कारण हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सहायता अभियान (यूएनएएमए) ने शहरी इलाकों में लड़ाई को तत्काल बंद करने का आह्वान करते हुए कहा कि आम नागरिक हिंसा का दंश झेल रहे हैं। हाल की एक खबर के अनुसार, लश्करगाह में पिछले 24 घंटों में 40 आम नागरिक मारे गए और 118 घायल हो गए।

कंधार में कम से कम पांच आम नागरिकों की मौत हो गयी और 42 जख्मी हो गए। महासचिव गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बुधवार को एक दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम लश्करगाह में लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं जहां लड़ाई के कारण हजारों लोग फंसे हो सकते हैं।'' दुजारिक ने कहा कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अफगानिस्तान में संघर्ष में करीब 3,60,000 लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। करीब 50 लाख लोग 2012 से अब तक विस्थापित हो चुके हैं। साल के पहले छह महीनों में स्वास्थ्य केंद्रों पर हमलों ने अफगानिस्तान में 2,00,000 लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा, ''हम सभी संघर्षरत पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन करते हुए नागरिकों, सहायता कर्मियों और स्कूल तथा अस्पताल समेत असैन्य बुनियादी ढांचे की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं।''

उन्होंने बताया कि एक अगस्त को कंधार में 2,000 से अधिक लोगों को भोजन, पानी, सफाई व्यवस्था और नकद सहायता मुहैया करायी गयी। अफगानिस्तान में ''भयानक हिंसा'' का सामना कर रहे बच्चों का जिक्र करते हुए दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) ने उस रिपोर्ट पर आक्रोश जताया है जिसमें फरयाद प्रांत में 12 वर्षीय लड़के से सरकारी विरोधी एक समूह के एक सदस्य ने क्रूरता से मारपीट की। यूनिसेफ ने कहा कि इस हिंसा से लड़का सदमे में है और स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर उसे, उसके परिवार को सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, असैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के 2 अंशकालिक सदस्यों पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप

नई दिल्ली । दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के 2 अंशकालिक सदस्यों पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने शिकायत की है कि सदस्य रवि शंकर और अनीता उज्जैनवाल ने सलाहकार समिति में 100 लोगों की सदस्य के रूप में नियुक्ति की है, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर आयोग के सचिव एवी प्रेमनाथ ने दोनों सदस्यों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।

संजय गहलोत ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दोनों सदस्यों ने नियुक्त किए गए लोगों को वेतन-भत्ते का लालच देकर काफी पैसे भी वसूले हैं। उन्होंने दोनों सदस्यों को हटाने और इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए भी लिखा है। इस मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को फोन कर और वाट्सएप मैसेज भेजकर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कोई पक्ष नहीं मिला।

आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब साढ़े तीन साल पहले रवि शंकर और अनीता उज्जैनवाल को अंशकालिक सदस्य के तौर पर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्त किया था। गत दिनों जब आयोग के चेयरमैन का पद रिक्त था, तब उक्त दोनों सदस्यों ने आयोग की सलाहकार समिति में सदस्यों की नियुक्ति की। इन्हें निगम के विभिन्न जोन में तैनाती दी गई।

संजय गहलोत ने जब विगत जून में फिर से चेयरमैन का पद संभाला तो उन्होंने दोनों सदस्यों के खिलाफ आयोग के सचिव से शिकायत की। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता है।

रवि शंकर (अंशकालिक सदस्य, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग) के मुताबिक, आरोप निराधार हैं। आयोग की बेहतरी के लिए लोगों को सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। मेरे पास इन्हें नियुक्त करने का अधिकार है। किसी को कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

अनीता उज्जैनवाल (अंशकालिक सदस्य, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग) का कहना है कि कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया है। आयोग के प्रविधान के तहत ही लोगों की नियुक्ति की गई है। आयोग के चेयरमैन जो आरोप लगा रहे हैं, वह सरासर गलत है।

संजय गहलोत (अध्यक्ष, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग) का कहना है कि आयोग के इन दोनों सदस्यों द्वारा सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है, जिस पर मैंने कार्रवाई करने के लिए आयोग के सचिव से कहा है।

दिल्ली में युवा कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल; 589 लोग हिरासत में

नई दिल्ली । यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रायसाना रोड पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और पेगासस समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान 28 महिलाओं, 2 सांसदों और 2 विधायकों सहित कुल 589 लोगों को हिरासत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के आयोजक श्रीनिवास बीवी को विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी।

राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना- युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री सभी विषयों पर बोलते हैं लेकिन रोज़गार के बारे में वे एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोज़गार छीना गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का लक्ष्य भारत के युवाओं की आवाज़ को दबाने का है। क्योंकि ये जानते है कि जिस दिन भारत के युवाओं ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी उसी दिन केंद्र सरकार ख़त्म हो जाएगी। बताया जा रहा है कि संसद घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से राजधानी के अशोक रोड और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक जाम लग गया। जाम की वजह रायसीना रोड पर भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध को बताया जा रहा है।

संक्षिप्त खबर

इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, विदेशी महिलाओं के जरिये कराते थे तस्करी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. नाइजीरिया से ऑपरेट हो रहे इस ड्रग्स रैकेट में 4 करोड़ रुपयों की कीमती हेरोइन बरामद की गई है. क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स की खेप के साथ दो महिलाओं को भी द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वे पंजाब हरियाणा बरेली, मुंबई, कोलकाता में ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी थीं. पकड़ी गई एक महिला विदेशी है. जबकि दूसरी मधु नाम की महिला दिल्ली की रहने वाली है.

पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं अपने बाकी गैंग्स मेबर के साथ करोड़ों रुपयों की ड्रग्स की खेप अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर चुकी हैं. पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई है. 4 करोड़ रुपयों की हेरोइन पकड़े जाने को पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां कर सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया देशभर के सफाईकर्मियों के हितों से जुड़ा एक अहम कदम...

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम कदम के तहत केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले द्वारा 28 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए जवाब, जिसमें कहा गया कि बीते 5 वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजिंग से कोई मौत का मामला सामने नहीं आया है, को लेकर दायर एक एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एप्लीकेशन को स्वीकारते हुए मामले में भारत सरकार को भी पक्ष बनाए जाने के आदेश दिए. दरअसल, मंत्री के बयान के बाद एडवोकेट एवं सोशल एक्टिविस्ट अमित साहनी द्वारा 2019 की एक पेंडिंग याचिका में यह एप्लीकेशन दायर की गई थी. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एप्लीकेशन में उठाई गई मांग को स्वीकार कर लिया और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को मामले में पार्टी बनाने के आदेश जारी कर दिए. साथ ही अदालत ने इस एप्लीकेशन पर भारत सरकार को 13 सितंबर 2021 तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस एप्लीकेशन में सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई करने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है. इस आवेदन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के राज्यसभा में हाल में दिए उस बयान का जिक्र किया गया है कि पिछले पांच साल में ''मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई.'' एप्लीकेशन में दावा किया गया है कि केंद्रीय राज्यमंत्री द्वारा संसद के ऊपरी सदन में दिया गया बयान ''न केवल झूठा और गुमराह करने वाला है बल्कि यह हाथ से मैला ढोने के कारण जान गंवाने वाले लोगों, उनके परिवारों और अब भी यह काम कर रहे लोगों के प्रति असंवेदनशीलता और उदासीनता को दिखाता है.''

स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस चौकन्ना, आयुक्त राकेश अस्थाना ने उठाया ये बड़ा कदम

नई दिल्ली. दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी करने एवं आतंकवाद संबंधी खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अपने समकक्षों के साथ अंतरराज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की. जबकि इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड , बिहार, राजस्थान, चंडीगढ एवं जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों एवं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया. इसके अलावा मेरठ (उत्तर प्रदेश) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , रोहतक (हरियाणा) के अतिरिक्त महानिदेशक , नोएडा एवं गुरुग्राम के पुलिस आयुक्तों, रेवाड़ी के पुलिस महानिरीक्षक और उत्तराखंड के पुलिस उपमहानिरीक्षक ने इस बैठक में हिस्सा लिया.

दिल्ली पुलिस का ये है मकसद- दिल्ली पुलिस के प्रमुख ने किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए किरायेदारों के सत्यापन, होटलों एवं अतिथिघरों में तलाशी जैसे रोकथाम उपायों के साथ-साथ आतंकवाद निरोधक चौकसी एवं राष्ट्रीय राजधानी में हथियारों, अपराधियों एवं मादक पदार्थों के पहुंचने से रोकने के लिए सीमा पर तलाशी पर जोर दिया है.

कमिश्नर ने जारी किया अलर्ट- बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की राजधानी में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा विशेष अलर्ट जारी किया गया है. कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हाल ही में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे. इसमें विशेष तौर पर ड्रोन पर निगरानी रखने कहा गया था. बगैर अनुमति के ड्रोन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. बावजूद इसके लाल किले के ऊपर से ड्रोन उड़ने को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

ऐसे कानून से या फायदा जो इंसाफ न दिला सके, दिल्ली में बच्ची से दरिंदगी पर बोलीं निर्भया की मां

नई दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के कैंट इलाके में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला एक बार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ अब इसमें सामाजिक संस्थानों की भी एंट्री हो गई है। इस बीच बृहस्पतिवार दोपहर में निर्भया की मां भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्भया केस के बाद सख्त कानून बनाया था, लेकिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कानून को बच्चियों को न्याय न दिला सके और गुनहगारों को सजा न दिला सके। उन्होंने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर कानून ढंग से काम करता ऐसी नौबत नहीं आती।

दोषियों को हो फांसी की सजा

निर्भया की मां ने कहा कि अगर बच्ची को करंट लगा था तो उसका दाह संस्कार जल्दबाजी में क्यों किया गया? नियम तो

कहता है कि उन्हें पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मां-बाप से झूठ बोलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा मिले।

गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2012 गैंगरेप के बाद हुए धरना प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने दुष्कर्म मामलों में कानून पर विचार के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रजातंत्र के जरूरी हिस्से पुलिस, जनप्रतिनिधि कानून, न्यायिक व्यवस्था, सैन्य विशेषाधिकार कानून आदि में सुधार की वकालत की थी।

आरोप है कि दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को बिजली का करंट लगने से लड़की की मौत हो गई। चारों आरोपितों राधेश्याम, सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप का कहना है कि उन्होंने मां-बाप को कलाई और कोहनी पर जलने के निशान भी दिखाए थे। इसके बाद बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। इस बीच मां-बाप के एतराज पर मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के डीसीपी इंजीत प्रताप सिंह का कहना है कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान श्मशान के 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम, सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप के रूप में हुई है।

हवा और एसी से फैल रहा कोरोना संक्रमण ! दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस के खतरा के देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य को निर्देश दिया कि वे बिना वेंटिलेशन वाले एयर कंडीशनिंग वाले बंद स्थानों में कोरोना वायरस संक्रमण के हवा में प्रसार के जोखिम के खिलाफ चेतावनी देने वाली याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानें।दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सिंह की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संबंध में तय किया जाए।

अदालत ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा विचार किया जाना है और एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है, इसलिए इसे जिम्मेदार संस्थाओं के हवाले किया जाए। अधिवक्ता युगांश मित्तल और अमित शाही, सिंह ने दावा किया कि हवाई मार्ग से फैलने वाले कोविड-19 वायरस के खतरे को कम करने के लिए एयर कंडीशनिंग वाले भवनों में ताजी हवा में परिवर्तन प्रदान किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि खुली खिड़कियों या उचित कमजोर वेंटिलेशन वाले एयर कंडीशनर का उपयोग करना गेम-चेंजर के रूप में काम कर सकता है।

बता दें कि पिछले साल देश भर में कोरोना वायरस के खतरा के देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया था कि सीजन के दौरान कोर्ट के अंदर एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम से संक्रमण के बढ़ते खतरा के मद्देनजर कोर्ट ने ये फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट प्रांगण में सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम को बंद ही रखा जाएगा। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया था, जिसमें उन इमारतों में सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम ना चलाने की मांग की गई थी, जहां पर लोग अभी भी आवश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं।

अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज

नई दिल्ली । किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार और उनकी नीतियों से नाराज हैं, इस वजह से वो आए दिन सरकार की नीतियों और रीतियों की आलोचना करते रहते हैं। अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल ट्विटर पर वो अक्सर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। ताजा मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर तंज कसा है। एक विज्ञापन की फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि मोदी-योगी का तो बस थैला है, इसके अन्दर अनाज तो ाकिसान ने भरा है। ये लिखते हुए उन्होंने तमाम मीडिया संस्थानों को टैग भी किया है। .

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तीन सीमाओं पर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को अब 8 माह से अधिक का समय हो चुका है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालकर जिस तरह से उत्पात मचाया वो किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद भी किसानों और केंद्र सरकार ने कई दौर की बातचीत हो चुकी है मगर उन बातों का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की बात हो रही है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है मगर किसान निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं।

इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर किसानों के बीच में अपनी बात रखेंगे और सरकार की नीति व काम को लेकर बात करेंगे। इसके लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत का आयोजन होगा उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

किसान नेता राकेश टिकैत समय-समय पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और अपने अंदाज में धमकाते भी रहते हैं। नई धमकी के तहत कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी -बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई न रहे। राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ समय पहले ये लाइनें भी ट्वीट की थी।

खेल का मैदान बचाने के लिए 3 महिला कबड्डी खिलाड़ी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। एक तरफ देश की लड़कियां टोक्यो ओलंपिक खेलों में मेडल लेकर आ रही हैं वहीं दूसरी ओर दिल्ली में खेल के मैदान को बचाने के लिए खिलाड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं. हाल ही में आयानगर की तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने आयानगर में ग्राम सभा की जमीन पर बने खेल के मैदान को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कबड्डी की खिलाड़ी अंजलि, प्राची बिष्ट और मुस्कान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर खेल के मैदान को मुक्त करने की मांग की है. तीनों महिला खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई कर रहीं दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयानगर में सरदार पटेल पार्क ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है. लंबे समय से आसपास के सभी गांव (आया नगर, घिटोरनी, जोनापुर, मण्डी , गदाई पुर, सुल्तानपुर आदि) की लड़कियां इस जमीन को कबड्डी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए उपयोग करती हैं. पहले ये जगह बहुत उबड़-खाबड़ थी. जिसे ठीक करने का बीड़ा इन लड़कियों ने ही उठाया. यहां मिट्टी डालने के साथ ही पौधे लगाने का

काम भी इन्होंने ही किया और खेल के उपकरण भी लगाए.

बिना किसी सरकारी सहयोग के खुद के पैसे मिलाकर इसमें कबड्डी के दो कोच भी रखे. इसके साथ ही साल 2011 में सरकार को विनती पत्र लिखकर कहा कि आसपास के किसी भी गांव में लड़कियों के खेलने के लिए जमीन नही है. अब अगर इस जमीन को खेल के मैदान में बदला गया है और 15 साल से यहां खेल की तैयारी की जा रही है तो इस छोटी सी जमीन को पार्क के नाम से आवंटित कर दिया जाए.

एडवोकेट विनीत मल्होत्रा व अंजू जैन ने बताया कि लड़कियों की इस मांग पर इस जमीन को साल 2012-13 में डिविजनल कमिश्नर दिल्ली सरकार ने पार्क के लिए आवंटित कर दिया. साथ ही एमसीडी ने यहां लाइट भी लगवाई. इसके बाद से यहां लडकिया इस जगह पर खेलती है और नेशनल कबड्डी भी खेल कर आई हैं. कई खिलाड़ी आगे भी खेलना चाहती हैं.

इस जमीन पर विवाद का मामला तब शुरू हुआ जब इस जमीन के पीछे की तरफ स्कूल के लिए 2013 में 50 बीघा जमीन अलॉट हुई लेकिन 2018 में बीडीओ आफिस द्वारा कुछ क्लेरिकल गलती के कारण ये पार्क वाला खसरा 1592/2 (2 बीघा) भी उसी लिस्ट में लिख कर भेज दिया गया. चूंकि ये जमीन पहले ही सरकार द्वारा पार्क के लिए दी गयी थी तो इसमें ओवरलैपिंग को गई और सरकार की ओर से इस जमीन को खाली कराने की बात की गई है. जिसके बाद निगम पार्षद वेदपाल से मिली महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने कहा कि आसपास कोई खेल का मैदान या स्टेडियम न होने के कारण उनके खेलने के लिए कोई जगह नहीं होगी और उन्हें खेलना बंद करना पड़ेगा क्योंकि परिवार वाले ज्यादा दूर उन्हें नहीं भेजेंगे. इसके बाद निगम पार्षद ने भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस जमीन को छोड़ने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई न होते देख अब दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन उत्पीड़न के मामले, 31 राज्यों में होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले की घटना के बाद से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी जल्द से जल्द देने की मांग भी जोर शोर से की जा रही है. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम भी उठाते हुए देश में स्थापित सभी स्पेशल पोक्सो कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने का मंत्रीमंडलीय फैसला भी किया गया है. देश में बढ़ते यौन उत्पीड़न और यौन अपराध के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इस तरह की कोर्ट्स का आगे भी जारी रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है. इन कोर्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने 1572.86 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की है जोकि निर्भया फंड के जरिए जारी की जाएगी.

बताते चलें कि देश में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराध और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर स्पेशल पोक्सो कोर्ट्स सहित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्थापित की गई थी. केंद्र सरकार ने इन सभी कोर्ट को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है. इतना ही नहीं सरकार जिन राज्यों में इस तरह की कोर्ट नहीं है वहां भी जल्द से जल्द इनकी स्थापना कराना चाहती है.

देश के 31 राज्यों में योजना का विस्तार करने की तैयारी- इस बीच देखा जाए तो मौजूदा समय में विशेष पोक्सो कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 28 राज्यों में स्थापित की हुई हैं. वहीं अब केंद्र सरकार सभी 31 राज्यों में इस तरह की कोर्ट स्थापित करने के लिए योजना तैयार कर चुकी है. देश के 31 राज्यों में इस तरह की कोर्ट स्थापित की जा सकेंगी. यह सभी राज्य केंद्र की इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं. सरकार आने वाले समय में जल्दी 31 राज्यों में इस योजना का विस्तार करेगी.यह देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है.

योजना के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता.

दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की संख्या कम करना.

यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना और यौन अपराधियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करना.

इन मामलों की तेज अदालती प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करेगी.

31 मार्च, 2023 तक जारी रहेंगी स्पेशल पोक्सो व फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 389 विशेष पोक्सो कोर्ट्स सहित 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. और इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये) की धनराशि निर्धारित की गयी है. केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी. यह योजना 02 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी.

केंद्र का मानना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया गया है. बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने पहले ही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों और 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था. इस तरह की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के परीक्षण के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता थी, जो मुकद्दमे में तेजी ला सके और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके.

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू करने से फास्ट ट्रैक की स्थापना- ऐसे मामलों में अधिक कड़े प्रावधान, त्वरित सुनवाई और मामलों के निपटान के लिए, केंद्र सरकार ने ÷आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018÷ लागू किया और दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया. इससे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना हुई.

अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट समर्पित अदालतें हैं, जिनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है. इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं. असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है.

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एसडीएम के साइन को लेकर डीयू ने दूर किया स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ईडब्ल्यूएस कोटे से रजिस्ट्रेशन कराकर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन डीयू प्रशासन ने दूर कर दिया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एसडीएम के साइन के लिए स्थानीय प्रशासन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. सर्टिफिकेट में शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी के साइन मान्य होंगे.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. वेबसाइट में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एसडीएम के साइन होने चाहिए, तभी मान्य होगा. राज्यों में शासन ने अलग-अलग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है. इसी के तहत उत्तर प्रदेश में इसके लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है. तहसीलदार के साइन से ही सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं. डीयू में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे तमाम स्टूडेंट्स इस निर्देश के बाद अपने-अपने जिलों के एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं. गाजियाबाद के एसडीएम सदर डीपी सिंह ने बताया कि उनके पास रोजाना कई पैरेंट्स प्रार्थनापत्र लेकर आ रहे हैं, जो बच्चों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में साइन कराना चाहते हैं. वे बताते हैं कि यहां पर शासन ने तहसीलदार को अधिकृत किया है, इसलिए एसडीएम साइन नहीं कर सकता है. दूसरी ओर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन दूर करते हुए डीयू के डीन प्रो. राजीव गुप्ता बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले रहे छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. संबंधित राज्य ने जिस अधिकारी को इस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए अधिकृत किया है, डीयू उसी को मान्य मानेगा, लेकिन सर्टिफिकेट मौजूदा वित्तीय वर्ष का होना

संपादकीय

अमेरिका की नाकामी का नतीज

अफगानिस्तान आज जिस संकट से जूझ रहा है, वह अमेरिका और तालिबान के दोहा समझौते की नाकामी का नतीजा है। तालिबान ने कभी संघर्ष विराम नहीं किया और न ही सत्ता साझा करने की उसकी कभी मंशा रही। नतीजतन, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की रवानगी के साथ उसकी हिंसा बढ़ती गई। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के करीब 150 जिलों पर तालिबान का कब्जा है और अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में वह है। फिर भी, यह कहना गलत होगा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की नागरिक सरकार बेअसर हो जाएगी और पूरे मुल्क पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा।

इसकी सबसे बड़ी वजह अफगान सुरक्षा बल हैं। वे वर्षों से तालिबान से लड़ रहे हैं। नाटो फौज से प्रशिक्षित ये सैनिक अपने दुश्मनों को हवाई हमलों से भी ढेर करने में माहिर हैं। करीब 40,000 से 50,000 विशेष कमांडो हैं अफगान सेना में। जाहिर है, तालिबानी लड़ाके इनके सामने नहीं ठहर पाएंगे। इसलिए तालिबान के लिए अफगानिस्तान के बड़े व प्रमुख शहरों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वास्तव में, अभी जिन 150 जिलों पर तालिबानी हुकूमत के दावे किए जा रहे हैं, वे बहुत छोटे-छोटे हैं। कई तो महज 10 मकान वाले जिले हैं, तो कुछ में एक से दो हजार की आबादी है। चूंकि अफगान सुरक्षा बल का पूरा ध्यान बड़ी आबादी वाले या महत्वपूर्ण इलाकों पर है, इसलिए इन छोटे हिस्सों पर तालिबान आसानी से कब्जा जमाने में सफल रहा। फिर, अमेरिका-तालिबान समझौते की शर्तों में यह भी शामिल था कि अमेरिकी सैनिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और तालिबान ऐसी किसी तंजीम को पनाह नहीं देगा या उससे नाता नहीं रखेगा, जो वाशिंगटन के खिलाफ है। यह शर्त तालिबान के भी मुफीद थी, क्योंकि वह नहीं चाहता कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में लौट आए। मगर अफगान सुरक्षा बल उसके निशाने पर बने रहे, जिसका माकूल जवाब अफगानी सैनिक भी देते रहे। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी सैनिक यहां जंग के मोर्चे पर तैनात नहीं थे, बल्कि वे अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दे रहे थे, गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे थे और अफगान वायु सेना की देख-रेख कर रहे थे। यानी, अफगान सुरक्षा बल पहले से ही तालिबान से लोहा ले रहे हैं।

फिर बड़ी चुनौती क्या है? दरअसल, तालिबान दोतरफा वार कर रहा है। वह अफगान सैनिकों पर हमले तो कर ही रहा है, उनमें फूट डालने की भरसक कोशिश भी कर रहा है। अफगान फौज में कबीलाई लड़ाके ही नहीं, मूल अफगानी, ताजिक, पश्तून जैसी कौमों के सैनिक भी हैं। तालिबान इनमें दरार डालने के प्रयास कर रहा है। जुलाई के शुरुआती हफ्ते में सैकड़ों अफगान सैनिकों के भागकर ताजिकिस्तान चले जाने की घटना तालिबान की सफलता मानी जा सकती है। तीसरी चुनौती सियासी मोर्चे पर है। अफगानिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व आज भी एक नहीं दिख रहा। वहां के नेताओं को समझना होगा कि उनकी आपसी तकरार सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ सकती है। यह स्थिति इस पूरे क्षेत्र के लिए सुखद नहीं है। मगर भारत को खासतौर से सावधान रहना होगा। यहां हमने न सिर्फ संचार लाइनें बिछाई हैं, सड़कें बनाई हैं, सलमा बांध, पुल आदि का निर्माण किया है, बल्कि कई ढांचागत परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग भी दिए हैं। इन तमाम निर्माण-कार्यों की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। चूंकि हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति अपनाते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों को ही इन परियोजनाओं की रक्षा करनी होगी। मगर एक सच यह भी है कि ये सभी निर्माण-कार्य हरेक शासन की जरूरत होते हैं, इसलिए तालिबान इनको शायद ही तत्काल नुकसान पहुंचाए। विश्व बिरादरी से अपने रिश्ते सुधारने के लिए तालिबान अलग-अलग देशों से कूटनीतिक संबंध बनाने के जतन भी कर सकता है। अभी तो वह अपने पुराने दौर जैसा कट्टर और बर्बर है। अपने अधीन इलाकों में शरीयत कानून लागू करने, लड़कियों के बाहर न निकलने, पुरुषों के दाढ़ी रखने, इस्लामी अमीरात बनाने और अन्य आतंकी जमातों के साथ अपने रिश्ते न तोड़ने का उसने एलान कर दिया है। मगर संभव है कि आने वाले दिनों में उइगर मुसलमानों को लेकर वह चीन से कोई कूटनीतिक समझौता करे। पाकिस्तान से भी वह अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है, क्योंकि तालिबानी लड़ाकों को इस्लामाबाद की पूरी शह हासिल है। अफगान सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े तालिबानी आतंकियों के पास से पाकिस्तानी नागरिकता के सुबूत तो मिले ही हैं।

तब भी, यही कहा जाएगा कि साल 1990 और आज के अफगानिस्तान में काफी फर्क है। नए अफगानिस्तान में अब लाखों लड़के-लड़कियां शिक्षित और प्रोफेशनल हैं। वे राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अहमियत अच्छी तरह समझने लगे हैं। ऐसे में, तालिबान की कट्टर सोच को वे बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। संभव है, यहां तलिबान के खिलाफ तकरार का दूसरा चरण, यानी 'रेजिस्टेंस 2.0' शुरू हो, जिसकी कमान नई पीढ़ी के हाथों में हो सकती है। यहां भारत के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फिर भी, नई दिल्ली को सबसे पहले पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार को रोकना होगा, जिसमें वह अफगानिस्तान में भारत की हार का दावा कर रहा है। यह दुष्प्रचार बताता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान छद्म तरीके से भारत से लड़ रहा था और अब तालिबान के बढ़ते प्रभाव से यह साबित होता है कि इस जंग में उसे जीत मिली है। जबकि, असलियत यही है कि भारत वहां किसी जंग में नहीं, बल्कि विकास-कार्यों में जुटा था, जिसे अफगान की हुकूमत और अवाम ने काफी पसंद भी किया है। भारत ने फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सक्रिय होने, संघर्ष विराम पर तत्काल सहमति बनाने, आसन्न राजनीतिक समझौते में पिछले दो दशकों की उपलब्धियों, मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा आदि सुनिश्चित करने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में ईरान, रूस, चीन जैसे देशों से लगातार संपर्क में हैं। यानी, भारत कूटनीतिक रूप से हालात सामान्य बनाने के प्रयास कर रहा है, मगर फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी कोशिशें कितना रंग लाएंगी। अच्छा तो यही होगा कि वहां संयुक्त राष्ट्र तुरंत दखल दे और अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम का संज्ञान लेकर सभी पक्षों को वार्ता कर मेज पर आने को बाध्य करे।

प्रवीण कुमार सिंह

अगले वर्ष 12वीं की परीक्षा कराने के लिए क्या हमारा तंत्र कहीं और बेहतर तरीके से तैयार नहीं होना चाहिए था

> इसमें प्रश्न पत्रों को रचनात्मक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि यह ओपन बुक परीक्षा जैसी होगी। साथ ही गड़बड़ियों को रोकने के लिए नकल रोधी सॉफ्टवेयर और निगरानी के अन्य तौर-तरीकों की मदद ली जा सकती है। ऐसा प्रचलन कई विकसित देशों में बहुत आम है।
> इन आमूलचूल परिवर्तन वाले प्रस्तावों के पीछे आधारभूत विचार यही है कि छात्रों को तनाव से मुक्ति वाला परिवेश प्रदान किया जाए। इस बीच यह स्मरण रहे कि बेचैनी की सबसे बड़ी वजह अनिश्चितता होती है। अकादमिक परिदृश्य से संदेह के बादल अभी तक छंटे नहीं हैं। यदि हमने तत्परता से प्रभावी कदम नहीं उठाए तो शिक्षा-दीक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता होना तय है। चीजों को सरल बनाने के उत्साह में क्या हम मूल तत्व की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं?

पिछले एक-डेढ़ साल के कोरोना काल में जीवन का शायद ही कोई अन्य पहलू इतने नाटकीय रूप से प्रभावित हुआ हो, जितना प्रभाव इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। कोविड महामारी ने स्कूल और कॉलेज के जीवन को एकदम बदलकर रख दिया है। कोरोना वायरस की भयावहता ने पारंपरिक शिक्षा एवं परीक्षाओं की राह बाधित की हुई है। परंपरावादी इससे मायूस हैं। ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति आदर्श तो नहीं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल सबसे उपयुक्त विकल्प लगती है। वैसे भी ऑनलाइन शिक्षण एवं मूल्यांकन की पद्धतियां अभी विकास के चरण में हैं। शिक्षा तंत्र के विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है कि इसमें कोई कारगर प्रणाली विकसित की जाए। इस पर आए सुझाव कुछ चिंताएं भले ही दूर करते हैं, किंतु कई प्रश्न भी उठाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि अहम मुद्दे अनसुलझे ही हैं।

भारतीय स्कूली छात्र के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही परीक्षा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सबसे स्वीकार्य कसौटी भी है। कोविड के कारण जहां इस साल 12वीं की परीक्षा रद कर दी गई वहीं अगले सत्र के लिए उसका प्रारूप बदल दिया गया। प्रस्तावित परीक्षा दो चरणों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन में आंतरिक आकलन और पूर्व परीक्षाओं को भी जोड़ा जा रहा है, मगर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 12वीं के परिणाम की महत्ता कम नहीं हुई है। यह बिंदु हमें देश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की वास्तविक समस्या से साक्षात्कार कराता है। कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी दबाव है। उनमें जितने आवेदन आते हैं, उस अनुपात में प्रवेश देना असंभव है। इसका परिणाम निकलता है आसमान छूती कटऑफ सूची में।

हर साल कुछ सबसे वांछित कॉलेजों में प्रवेश के लिए अर्हता सूची के 98 प्रतिशत या उससे भी अधिक के बेतुके स्तर पर जाने के समाचार आते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में प्रवेश के इच्छुक छात्र को 12वीं कक्षा में न केवल अंग्रेजी, बल्कि गणित, भौतिकी और अपने अन्य विषयों में भी 98 फीसद अंक लाने होंगे। इस तंत्र से मार खाए कुछ साधनसंपन्न छात्र स्नातक के लिए विदेश चले जाते हैं। असल में प्रतिभा पलायन का अभिशाप स्कूली शिक्षा की समाप्ति के साथ ही शुरू हो जाता है।

उच्च शिक्षा के लिए हमें और गुणवत्तापरक संस्थान चाहिए, जहां औसत अंक पाने वाले मध्यम प्रतिभा वाले छात्रों के लिए भी गुंजाइश हो। वर्तमान परिदृश्य में एक छात्र को प्रवेश मिलता है तो सैकड़ों वंचित रह जाते हैं। इसमें हमारे छात्रों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं। नए कॉलेजों के साथ यह भी उतना आवश्यक है कि वे छोटे और मझोले शहरों में हों ताकि देश भर के छात्रों का जमावड़ा कुछ चुंनदा मेट्रो शहरों में लगने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। इसमें दूरस्थ डिजिटल शिक्षा पथप्रदर्शक साबित हो सकती है। कनेक्टिविटी और सक्षमता जैसी चुनौतियों के बावजूद ऑनलाइन माध्यम में शिक्षा का कायाकल्प करने की अकूत संभावनाएं हैं।

भारतीय स्कूल प्रणाली में कई शिक्षा बोर्ड हैं। प्रत्येक राज्य का अपना बोर्ड है। सीबीएसई जैसा एक अखिल भारतीय बोर्ड भी है। विभिन्न बोर्ड में न केवल पाठ्यक्रम, बल्कि परीक्षा एवं मूल्यांकन के पैमाने भी अलग हैं, जबकि उनके छात्र उच्च शिक्षा के लिए समान सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ राज्य बोर्ड मूल्यांकन के लिए कहीं सख्त मापदंड अपनाते हैं, जहां सबसे मेधावी छात्र भी 90 प्रतिशत से अधिक अंकों के लिए संघर्ष करते हैं। इसके उलट सीबीएसई में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी हैरत में नहीं डालता। ऐसे में प्रत्येक बोर्ड में पर्सेंटाइल सिस्टम बराबरी वाली व्यवस्था बनाएगा। यह छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके तहत संभव है कि सख्त मूल्यांकन वाले किसी बोर्ड के 80 फीसद अंकों को भी सीबीएसई जैसे उदार बोर्ड के 90 फीसद से अधिक वरीयता दी जाए। कई विकसित देशों में इसका व्यापक उपयोग जारी है। दुर्भाग्यवश इस आवश्यक मानकीकरण या बराबरी की व्यवस्था को अभी भारत में आजमाया जाना शेष है।

महामारी के कारण पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं के रद होने की स्थिति में सीबीएसई ने छात्रों के मूल्यांकन का नया तरीका तलाशा है। दो चरणों वाली परीक्षा के साथ ही आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का प्रस्तावित प्रारूप निष्पक्ष और न्यायोचित नहीं लगता। छात्र किसी पूर्व परीक्षा के मुकाबले 12वीं बोर्ड परीक्षा में कहीं अधिक परिश्रम और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नई व्यवस्था में आंतरिक मूल्यांकन पर स्कूली पूर्वाग्रह हावी होकर पूरी प्रक्रिया को विरुपित भी कर सकते हैं। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कटौती और प्रश्न पत्र प्रारूप में परिवर्तन की पेशकश की है। परीक्षाएं वास्तव में छात्र के ज्ञान, समझ और अभिव्यक्ति के भाव को परखने के लिए होती हैं। नई प्रस्तावित योजना के बहु-विकल्पीय प्रश्नों में अभिव्यक्ति तो निश्चित रूप से नहीं परखी जा सकेगी। एक कटु सत्य यह है कि अधिकांश प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय सीबीएसई को उच्च मानकों के अनुरूप नहीं पाते। ऐसे में नई व्यवस्था से उसकी प्रतिष्ठा और घटेगी।

हम मान सकते हैं कि 2020-21 असामान्य साल रहा, लेकिन अगले वर्ष 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के लिए क्या हमारा तंत्र कहीं और बेहतर तरीके से तैयार नहीं होना चाहिए था? महामारी ने भले ही प्रत्यक्ष परीक्षा की राह रोक दी हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऑनलाइन मूल्यांकन प्रस्तावित व्यवस्था से कहीं बेहतर होता। यदि संसाधनहीन छात्रों को इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कुछ धनराशि खर्च भी करनी पड़े तो यह राज्य द्वारा किया गया सार्थक खर्च होगा। इसमें प्रश्न पत्रों को रचनात्मक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि यह ओपन बुक परीक्षा जैसी होगी। साथ ही गड़बड़ियों को रोकने के लिए नकल रोधी सॉफ्टवेयर और निगरानी के अन्य तौर-तरीकों की मदद ली जा सकती है। ऐसा प्रचलन कई विकसित देशों में बहुत आम है।

इन आमूलचूल परिवर्तन वाले प्रस्तावों के पीछे आधारभूत विचार यही है कि छात्रों को तनाव से मुक्ति वाला परिवेश प्रदान किया जाए। इस बीच यह स्मरण रहे कि बेचैनी की सबसे बड़ी वजह अनिश्चितता होती है। अकादमिक परिदृश्य से संदेह के बादल अभी तक छंटे नहीं हैं। यदि हमने तत्परता से प्रभावी कदम नहीं उठाए तो शिक्षा-दीक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता होना तय है। चीजों को सरल बनाने के उत्साह में क्या हम मूल तत्व की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं?

दलित समाज ने जैसे कांग्रेस को छोड़ दिया, उसी की पुनरावृत्ति वह आज अस्मिता की राजनीति करने वाले दलों के साथ कर रहा है

बीते दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में घटित घटनाएं दलित राजनीतिक विमर्श में नए रुझान का संकेत करती हैं। इसमें एक प्रश्न यही उभरा है कि क्या अब दलितों को अस्मिता से अधिक आकांक्षाएं आकर्षित कर रही हैं? बिहार में दलित राजनीति की अगुआ मानी जाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में आंतरिक उठापटक चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में रामअचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे कई कई दलित नेताओं को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई 'अंडर करेंट' है? विगत 74 वर्षों में बाबू जगजीवनराम को छोड़ कोई दलित नेता राष्ट्रीय स्तर पर पनप नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में मायावती और बिहार में रामविलास पासवान को आंशिक सफलता ही मिली। वैसे मायावती ने 2007 में प्रभावी 'सोशल इंजीनियरिंग' द्वारा समावेशी राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और सभी वर्गों के वोट से प्रदेश में सरकार बनाई। हालांकि अपने प्रयोग को वह बहुत आगे नहीं ले जा सकीं और राष्ट्रीय राजनीति की राह में भटक गईं। वहीं पासवान स्वयं निर्वाचित होते रहे, पर बिहार में दलितों को लामबंद नहीं कर सके और पासी-समाज तक ही सीमित होकर रह गए। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कोई दलित नेता राष्ट्रीय राजनीति तो दूर अपने प्रदेश में ही पूरी तरह स्थापित क्यों नहीं हो पाता? इसके तीन कारण तो बिल्कुल स्पष्ट हैं।

पहला यही कि दलित समाज बेहद विभक्त है। उसकी आंतरिक सामाजिक संरचना में उतना ही भेदभाव है जितना बाह्य समाज में। जाटव और पासी, पासी और वाल्मीकि, वाल्मीकि और डोम और ऐसे ही अनेक दलित समुदाय एक मंच पर नहीं आते। अधिकांश विमर्श दलित बनाम गैर-दलित पर ही केंद्रित रहता है। विश्लेषक 'दलित राजनीति' की बात करते हैं, लेकिन उनके विश्लेषण गलत हो जाते हैं, क्योंकि वे दलितों को समरूप समाज मानकर चलते हैं। कोई भी दलित या गैर-दलित नेता दलितों की आंतरिक सामाजिक संरचना की पदसोपानीयता और विसंगतियों को नहीं उठाता। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक 'दलित राजनीति' केवल सहयोगी राजनीति के रुप में ही क्रियाशील हो पाएगी, 'स्वायत्त-राजनीति' के रूप में नहीं।

दूसरा कारण यही है कि दलित समाज की आंतरिकपदसोपानीयता उसे समरूप समाज के रूप में लामबंद नहीं होने देती। यदि उप्र में जाटव केंद्रित दलित राजनीति है तो बिहार में पासी या मुसहर केंद्रित। पंजाब में सर्वाधिक 32 फीसद दलित हैं, लेकिन कोई दलित राजनीति की बात नहीं करता? कांशीराम तो होशियारपुर, पंजाब से थे। फिर भी वह वहां दलितों में पैठ नहीं बना सके? कारण स्पष्ट है कि वहां दलित समाज वाल्मिकी, रविदासी, कबीरपंथी, मजहबी सिख आदि में बंटे हुए हैं, जिनमें रोटी-बेटी का संबंध भी नहीं होता। क्या ऐसे विभक्त समाज में दलितों को लामबंद कर 'अस्मिता' आधारित राजनीति हो सकती है? क्या इसीलिए मायावती को पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल के साथ गठबंधन करना पड़ा? संभवतः इसी कारण भाजपा ने तुरुप का पत्ता चला है। भाजपा ने राज्य में दलित मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। यदि दलितों की राजनीतिक लामबंदी और सशक्तीकरण से उनके आंतरिक सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जा सके तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा।

तीसरा पहलू यही है कि दलित राजनीति स्वभाव से ही अस्मिता अर्थात 'पहचान की राजनीति' को स्वीकार करती है। किसी दल पर जब यह ठप्पा लग जाता है कि वह दलित अस्मिता को ही तरजीह देता है तो समाज के अन्य वर्ग उससे कटने लगते हैं। इससे समावेशी राजनीति की संभावना खत्म हो जाती है। मायावती ने यह मिथक 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में तोड़ा जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग द्वारा 'सैंडविच' गठबंधन बनाया। इसमें उन्हें सैंडविच के दो छोर की तरह न केवल ब्राह्मणों और दलितों का समर्थन मिला, वरन अंदरूनी फिंलग के रूप में समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन मिला। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान के दौरान मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के प्रति मुझे श्रोताओं में काफी उत्सुकता, आशा और रोमांच दिखा। उनमें मायावती को भावी राष्ट्रीय नेता के रूप में देखने की इच्छा थी, लेकिन मायावती अपनी सोशल इंजीनिर्यरंग को आगे न ले जा सकीं। वह अस्मिता की राजनीति और समावेशी राजनीति में समन्वय न कर सकीं। दलितों को लगा कि उनकी 'अपनी' सरकार बनने के बावजूद वे सत्ता से बाहर हो गए, क्योंकि मायावती ने ब्राह्मणों, मुस्लिमों आदि को सत्ता में ज्यादा भागीदारी दे दी थी। वहीं से दलितों का 'अस्मिता' से मोहभंग हो गया और उन्हें अपनी आकांक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण लगने लगीं। पिछले एक-डेढ़ दशक में यह प्रवृत्ति बढ़ी है और आज दलित समाज अस्मिता से ऊब चुका है। उसे अब अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी हैं।

बेलगाम तालिबान

भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बुधवार को अफगानिस्तान पर काबिज होते जा रहे तालिबान को कड़ी हिदायतें दीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का बलपूर्वक कब्जा उस देश के लिए बर्बादी का सबब बन सकता है और खुद तालिबान भी ऐसा करके कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिका की ओर से यह सलाह ऐसे समय आई है, जब तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जा करने के अभियान में लगे हुए हैं और आसपास के ज्यादातर प्रभावशाली देश उन्हें रोकने का इंतजाम करने के बजाय उनसे हाथ मिलाने की तरकीबें खोज रहे हैं। ब्लिंकेन ने नई दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अमेरिका भले अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटा रहा है, लेकिन वह अपनी नजरें वहां से नहीं हटाएगा। अमेरिका का यह दावा खोखला है। सच तो यह है कि 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद उसने अफगानिस्तान में अल कायदा और उसके आतंकवादियों को पनाह देने वाले तालिबान के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, उसमें आखिरकार उसे हथियार डालने का फैसला करना पड़ा। बेशक, दो दशक लंबी चली इस लड़ाई में उसने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के साथ उसके आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने में सफलता पाई। लेकिन न तो वह अल कायदा को खत्म कर पाया और ना ही तालिबान को कमजोर।

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के कई सूबों में अल कायदा का नेटवर्क मौजूद है। तालिबान पहले की तरह इन आतंकवादियों के संरक्षक बने हुए हैं। ऐसे संगीन हालात के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना बुलानी शुरू की तो तालिबान ने देश में अधिक से अधिक हिस्से पर कब्जे की मुहिम और तेज कर दी। आज अगर इस पूरे क्षेत्र में तालिबान के कारण अस्थिरता की स्थिति बन रही है तो उसके लिए अमेरिका ही दोषी है। इतना ही नहीं, उसके इस फैसले के कारण अफगानिस्तान में चीन का दखल बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है। ब्लिंकेन जब भारत से तालिबान को चेतावनी दे रहे थे, तभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अगुआई में चीन गया तालिबान का एक डेलीगेशन वहां के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहा था।

जहां चीन ने तालिबान को अफगानिस्तान की एक अहम सैनिक और राजनीतिक ताकत करार दिया, वहीं तालिबान ने आश्वस्त किया कि वह अफगानिस्तान की भूमि का चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। इस बीच काबुल में अफगान सरकार की बेबसी बढ़ती जा रही है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर वैश्विक समुदाय को आगाह किया है कि यह बीसवीं सदी का तालिबान नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क और बहुराष्ट्रीय अपराधी नेटवर्क का एक मिला-जुला रूप है। इसलिए इसे रोकना ही होगा।

अब तो हमारे नीति-नियंताओं को शाहबानो प्रकरण के दुस्वप्न से उबर ही जाना चाहिए

> सुप्रीम कोर्ट और दूसरे विद्वानों ने इस कमी की ओर बार-बार इशारा किया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ढाक के वही तीन पात रहे, क्योंकि वे शाहबानो प्रकरण से सहमे हुए थे। इसके पहले अन्य विद्वानों ने भी इसकी वकालत की है। न्यायमूर्ति मुहम्मद करीम छागला ने मोतीलाल नेहरू व्याख्यानमाला में, प्रोफेसर ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' (1977) में तथा न्यायमूर्ति एमयू बेग ने 'इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म' (1973) में भी संविधान के अनुच्छेद 44 को अमली जामा पहनाने का आह्वान किया, किंतु शाहबानो प्रकरण के दुस्वप्न से अभी भी कोई उबरने को तैयार नहीं है।

अदालत ने एक बार फिर सरकार से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का आग्रह किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत बताया है, ताकि हमारा समाज और अधिक समरस हो सके और उसमें एकजुटता बढ़ सके। संविधान का अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए। ऐसी व्यवस्था बनाए, जो मानवीय गरिमा का सम्मान करती हो, उसे सुरक्षा बोध दे और सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरे।

दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस पवित्र मंशा को आगे बढ़ाने के बजाय हमने अपनी फितरत के मुताबिक एक हौवा खड़ा कर दिया। उस पर तार्किक बहस करने के बजाय उसे सांप्रदायिक रूप देकर अछूत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का आग्रह बेकार गया। इस मामले में तो हम लोकशाही की महान परंपराओं से भी मुंह चुराने लगते हैं। इस विषय पर स्वस्थ बहस करने के बजाय इसके प्रस्तावकों की लानत-मलानत करने लगते हैं और उसे तब तक जारी रखते हैं जब तक सामने वाला थक हार कर बैठ न जाए।

संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी उपासना पद्धति से नहीं है, बल्कि

इसका संबंध इंसानियत से है। निस्संतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है तो आखिर इससे किसी उपासना पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने के बजाय गुजारे-भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें मजहब कहां से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदगी नहीं, अपितु गर्व होना चाहिए।

आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले, पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पति-पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें भरण पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा की शुरुआत हुई। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को तरजीह दी गई, पर वोट बैंक खिसकने के स्वार्थी सोच के कारण दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हो सका। उन्हें बेहतर होने के मौके से लगातार वंचित रखा गया। संविधान का अनुच्छेद 44 और अदालतों के कई निर्देश भी इस सोच पर बेअसर रहे।

आधुनिक सोच का लाभ केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रहे और वह दूसरे मतावलंबियों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें लगातार कोशिश करती रही हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में तय की गई राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह मात्र बनकर रह गई है। सरकारी उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा था कि मुस्लिम समाज को इस मामले में पहल करने की जरूरत है, ताकि प्रगति की दौड़ में वे दूसरों से पीछे न रहें। हैरानी की बात यह है कि शाहबानो के जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया, उसके दुष्प्रचार ने सबसे अधिक चोट समान नागरिक संहिता की पहल को पहुंचाई।

शाहबानो प्रकरण के बाद सरला मुदगल (1995) तथा लिली थामस (2000) जैसे कई प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक कानून के नहीं होने के दोषों को उजागर करते हुए इसका तुरंत क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। वैवाहिक मामलों में वैयक्तिक विधि के दुरुपयोग से विचलित होकर अदालत ने कहा कि अब तो इसका दुरुपयोग कानून को धोखा देने के लिए होने लगा है। जब वैवाहिक साथी से छुटकारा पाना हो तो कुछ समय के लिए अपना मजहब बदलकर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि दूसरे मजहब से जुड़े कानून में उसे मान्यता दी गई है। उसके बाद अपनी मर्जी से तलाक देकर उस महिला से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उस मजहब का कानून इसकी इजाजत देता है।

सुप्रीम कोर्ट और दूसरे विद्वानों ने इस कमी की ओर बार-बार इशारा किया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ढाक के वही तीन पात रहे, क्योंकि वे शाहबानो प्रकरण से सहमे हुए थे। इसके पहले अन्य विद्वानों ने भी इसकी वकालत की है। न्यायमूर्ति मुहम्मद करीम छागला ने मोतीलाल नेहरू व्याख्यानमाला में, प्रोफेसर ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' (1977) में तथा न्यायमूर्ति एमयू बेग ने 'इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म' (1973) में भी संविधान के अनुच्छेद 44 को अमली जामा पहनाने का आह्वान किया, किंतु शाहबानो प्रकरण के दुस्वप्न से अभी भी कोई उबरने को तैयार नहीं है। समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर पंथनिरपेक्ष हितचिंतकों को आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करने जरूरत है, ताकि हम एक प्रगतिशील समाज के रूप में एकजुट हो सकें।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

अयोध्या पहुंचे सीएम योगी , बोले-संतों से भेंट करने के साथ करेंगे रामलला का दर्शन-पूजन

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तथा भूमि पूजन का एक वर्ष पूरा होने पर यहां पर भव्य आयोजन होगा। गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या में यजमान की भूमिका में रहेंगे। अयोध्या में बीते वर्ष पांच अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तथा शिलान्यास के एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचे हैं। वह निर्धारित कार्यक्रम से 45 मिनट पहले ही रामनगरी पहुंच गए। हैलीपेड पर उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में तीन घंटा रहेंगे। इस दौरान संतों से भेट भी होगी। इसके साथ ही रामलला का दर्शन तथा पूजन भी होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच अगस्त को भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर भूमि पूजन की एक वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आयोजन की तैयारी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी यजमान की भूमिका में होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख संत-महंतों भी शामिल होंगे। वह यहां पर अन्न महोत्सव के अतिरिक्त राम जन्म भूमि जाएंगे, जहां निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। वह इस दौरान मंदिर परिसर में रखे गए राम मंदिर के नए माडल की पूजा करेंगे।

अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम दोपहर दो बजे कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी के बाद मंदिर के नवीन माडल को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा जाएगा। यह माडल अभी तो दर्शन मार्ग पर ही रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला भोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। भूमि पूजन की वर्षगांठ पर वैकल्पिक गर्भगृह और परिसर को भी सजाया गया है। योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को के परिसर भ्रमण के दौरान श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय सहित अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे। चंपत राय उन्हें निर्माण की प्रगति की जानकारी देंगे।

50 माह के दौरान 29वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को अयोध्या आ रहे हैं। वर्ष 2017 से ही प्रत्येक वर्ष छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव की परंपरा डालने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या को वैश्विक क्षितिज पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आएंगे। दोपहर 12.05 बजे रामकथा पार्क में निर्मित हेलीपैड पर उनका हेलीकाप्टर उतरेगा। वह वासुदेवघाट पर आयोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री प्रदेश के जिन छह जिलों में वर्चुअल संवाद राशन कार्ड धारकों से करेंगे, उनमें अयोध्या, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर, सुल्तानपुर शामिल है। यहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अन्न वितरण कार्यक्रम में दोपहर 12.15 बजे से 2.15 बजे तक रहेंगे। दोपहर 2.30 बजे 2.45 बजे तक मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने रामजन्मभूमि जाएंगे। दोपहर 2.45 बजे वह रामकथा पार्क के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3.05 बजे वह लखनऊ के लिए उड़ेंगे। मुख्यमंत्री का अधिकारिक कार्यक्रम जिला प्रशासन को मिल गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर जिले के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश आ चुके हैं। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रमण कर सीएम के दौरे की तैयारियों को उन्होंने अंतिम रूप दिया।

पीएम नरेंद्र मोदी के दूत की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्य अयोध्या निर्माण के राम-काज में हनुमान जी की तरह समर्पित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत की भमिका में कोई कसर नहीं छोड़ी और रामनगरी को उनकी मंशा के अनुरूप आकार देने की योजना के अग्रदूत बनकर उभरे। रामनगरी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव गुरु और दादा गुरु के जमाने का ही है। गुरु अवेद्यनाथ के साथ वे एक दशक तक अयोध्या आते- जाते रहे, राम मंदिर सहित स्थानीय संतों से आत्मीयता उन्हें गुरु से ही विरासत में मिली। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनका रामनगरी से जुड़ाव और निखर कर सामने आया। नौ नवंबर 2019 को रामलला के हक में आए निर्णय के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह भी रामनगरी की ओर केंद्रित हुई और उन्होंने रामनगरी को विश्व की शीर्ष सांस्कृतिक नगरी बनाने की परिकल्पना दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परिकल्पना को आाकार देने की राह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वह गत 50 माह के दौरान 29वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को अयोध्या आ रहे हैं। वर्ष 2017 से ही प्रत्येक वर्ष छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव की परंपरा डालने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या को वैश्विक क्षितिज पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे हैं और जल्दी ही वह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में वे रामभक्तों को दिव्य-नव्य अयोध्या की सौगात देने की तैयारी में हैं।

दो दिनों तक घूम-घूम कर सीएम नीतीश ने लिया कोविड प्रोटाकाल का जायजा, संतुष्ट हुए तो दी छूट

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों का दौरा किया और कोविड प्रोटोकाल के पालन का जायजा लिया। अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने देखा कि लोग मास्क लगाने को लेकर कितने जागरूक हैं। विभिन्न स्तर पर सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है या नहीं। इस दौरान उन्होंने बोरिंग कैनाल रोड, राजापुल, गांधी मैदान, एक्जीविशन रोड, भट्टाचार्य रोड, कंकड़बाग मेन रोड, डाक्टर्स कालोनी, कंकड़बाग टेंपो स्टैंड, करबिगहिया एवं मीठापुर का भ्रमण कर जायजा लिया।

साथ में थी आला अधिकारियों की फौज- भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

एक दिन पहले कई जिलों से गुजरे थे सीएम - बता दें? कि एक दिन पूर्व तीन अगस्त को मुख्यमंत्री ने पटना से वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिले में कोविड प्रोटाकॉल का जायजा लिया था। सड़क मार्ग से निकले सीएम ने अधिकारियों से जरूरी फीडबैक भी लिया। चार अगस्त को पटना शहर का जायजा लेने के बाद शाम में सीएम ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की। इससे समझा जा रहा है कि सीएम ने स्वयं स्थिति का जायजा लिया।

स्वयं स्थिति का लिया जायजा तब की बैठक - गौरतलब है कि शाम में कोर ग्रुप की बैठक के बाद कोरोना गाइडलाइन में छूट की घोषणा की गई। इसमें सबसे अहम स्कूलों को खोले जाने के साथ ही सिनेमा हाल एवं माल खोलने की छूट को अहम माना जा रहा है। हालांकि यह ढील सात से 25 अगस्त तक के लिए दी गई है। इस बीच सरकार की नजर कोरोना के मामलों पर गंभीरता से रहेगी। विशेषज्ञों ने अगस्त में ही कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। इसको लेकर सरकार हर संभव उपाय भी कर रही है।

उपेंद्र कुशवाहा का पीएम मैटेरियल वाले बयान पर यू-टर्न, बोले- पीएम मोदी के बाद सीएम नीतीश

पटना। लोकसभा चुनाव में अभी तीन साल की देरी है, लेकिन बिहार की राजनीति में पीएम मैटेरियल की चर्चा होने लगी है। जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बता कर इसे मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह कह कर उपेंद्र कुशवाहा से अपनी असहमति जताई कि अभी प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। समझा जाता है कि बीजेपी के रूख को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपने वक्तव्य में संशोधन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बाद पीएम मैटेरियल हैं।

उपेंद्र कुशवाहा ने यूं लिया यू-टर्न

गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना से समानता आएगी। इससे गरीब व शोषित वंचितों को लाभ होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक न्याय के साथ विकास का माडल दिया है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार पीएम मैटेरियल हैं।

नीतीश ने भी नहीं दिखाई रूचि- बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के पीएम मैटेरियल वाले बयान को गंभीरता से लिया। पार्टी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस समय देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह कर बीजेपी की संभावित नाराजगी को कम करने की कोशिश की कि इन चीजों में उनकी कोई रूचि नहीं है। वे जितना बन सकता है, राज्य की सेवा कर रहे हैं। यही करना भी चाहते हैं। बीते सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उन्होंने यह टिप्पणी की।

लालू व चिराग ने भी की टिप्पणी- उधर, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के पीएम मैटेरियल वाले बयान पर बेहद संतुलित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसपर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचें। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट के नेता और सांसद चिराग पासवान की तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के इस बड़े पद पर काबिज होना चाहते हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले- बीजेपी में अपराधियों की भरमार, वो मैनीफेस्टो नहीं बनाते हैं मनीफेस्टो

लखनऊ। छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भव्य आयोजन किया है। समाजवादी पार्टी पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश के हर जिले में साइकिल रैली कर रही है। इसके साथ ही जनेश्वर मिश्र की जन्मभूमि बलिया में समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भी है। बलिया में जनेश्वर मिश्रा के घर शुभनथही से प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल रैली को रवाना करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के लिए नया नारा यूपी का यह जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश भी जारी किया। अखिलेश यादव ने कार्यालय में मीडिया को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर है। आज प्रदेश में जगह-जगह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। जिससे कि प्रदेश के हर कोने का हाल जान सकें। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाए थे और अब उसको आगे ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा में अपराधियों की भरमार है। वो मैनीफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। उनके लिए राजनीति एक व्यापार है। भाजपा की सरकार ने कोरोना के दौरान

लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता में भाजपा की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। यह सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दे पाई। साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के सभी कामों का उद्घाटन किया गया। इस सरकार ने हमारे कार्यकाल के दौरान कराए गए कामों नाम बदल दिया। इनको अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गरीबों की याद आने लगी।

लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय, विक्रमादित्य मार्ग से गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाते हुए गए। वहां पर उन्होंने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने कहा अभी तक हम 350 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे आज नाराजगी जनता की इतनी है कि हम 400 सीटें जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो भाजपा से बहुत नाराज है। इस बार तो इन्हें उम्मीदवार नही मिलेंगे। इस सरकार ने दलित, मुस्लिम, ब्राह्मणों को बहुत सताया गया है। अब सरकार को इनकी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि आज भी सपा के कामों के नाम बदल करके उद्घाटन कर रहे हैं। इन लोगों ने खुद काम नही किया। यह सरकार तो जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा अब अपराधियों को शामिल कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दवाओं की कालाबाजारी में नंबर वन है। यहां पर इलाज ना मिलने से लोगों की मौत हुई। लोगों को न तो अस्पताल में बेड मिले और न ही दवा मिली। प्रदेश में सम्मानित नागरिक बिना इलाज के मरे। योगी आदित्यनाथ सरकार तो प्रदेश के बेरोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन है। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त रही।

भाजपा सरकार को इसमें नम्बर वन- अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ प्रचार के दम पर योगी आदित्यनाथ सरकार अपने को नम्बर वन बता रही है। हकीकत तो यह है कि यह सरकार कुपोषण, गंगा किनारे लाशों को लकड़ी न देने, ऑक्सीजन न दे पाने, बेरोजगारी, युवाओं को लाठी से, नौकरी मांगने वालों को पीटने, महिला असुरक्षा, शव से कफन उतारने, बिना इलाज के लोगों को मारने तथा 1600 शिक्षकों को मौत के मुहाने में भेजने में नम्बर वन है। यह सरकार तो माननीय न्यायालय के आदेश न मानने में भी नम्बर वन है।

अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय से लखनऊ में साइकिल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग लोडर में साइकिल लादकर लोहिया पथ पर एकत्र थे। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के कारण लोहिया पथ पर भीषण जाम लगा था। यहां पर सपा कार्यकर्ताओं को साइकिल उपलब्ध कराई गई। सभी जिलों से कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान लोहिया पर के दोनों तरफ वाहन पार्क कर सपा के नेता साइकिल रैली में गए। जिसके कारण जाम लग गया। लोहिया पथ सहित तमाम जगहों पर स्वागत मंच बनाया गया।

लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी पे कहा कि उत्तर प्रदेश में आज 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ही अखिलेश यादव का शंखनाद है। आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़ा दिन है। प्रदेश में भाजपा ने विकास को बर्बाद किया है। अखिलेश यादव का सक्षम व्यक्तित्व ही प्रदेश को आगे ले जाने में कारगर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का आज रायबरेली दौरा है। वह रायबरेली में सपा की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां पर पार्टी के जिला कार्यालय से साइकिल यात्रा निकाली जाएगी।

हाकी में भारत की जीत पर सीएम नीतीश ने दी बधाई, मांझी ने ऐसे बयां की भावना

पटना। भारतीय पुरुष हाकी टीम की जीत पर हर ओर जश्न का माहौल है। हर तबका टीम इंडिया को बधाई दे रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी , विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत तमाम लोग भारतीय टीम की जीत पर अभिभूत हैं। वे अपने-अपने तरीके से टीम को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि जर्मनी को 5-4 के अंतर से हराकर भारतीय टीम ने ब्रांज मेडल पर कब्जा जमाया है।

नीतीश कुमार ने ट्वीट किया-टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे-मुख्यमंत्री ने अपने Tweet में लिखा है कि टोक्यो ओलिंपिक के हाकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हाकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मेरी कामना है कि टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे।

भारतीय टीम की जीत से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भावविह्वल हो गए। उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा कि आज से 41 साल पहले हाकी में मेडल मिला था। सोचता था कि इस जीवन में ओलिंपिक में हाकी मेडल मिलने पर राष्ट्रगान सुनने का मौका मिलेगा भी या नहीं। लेकिन आज अभिभूत हूं। आंखों में खुशी के आंसू हैं। उन्होंने टीम इंडिया को इसके लिए धन्यवाद देते हुए बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि भारतीय पुरुष हाकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद ब्रांज मेडल जीत कर पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों समेत टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि टीम इंडिया की जीत में बिहार के एक लाल ने भी अहम भूमिका निभाई है। मूल रूप से सिवान जिले के रहने वाले मिडफिल्डर विवेक सागर प्रसाद ने शानदार प्रदर्शन किया है। गांव में परिवार के लोग जश्न मना रहे हैं।

भागलपुर में नीतीश के मंत्री ने राजद पर फोड़ा बम, बोले- तेजस्वी बन रहे अपने मियां मिट्ठू

भागलपुर। राजद नेता तेजस्वी यादव के 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री बगेंगे। यह सवाल पर बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने यहां पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं। सूबे में ऐसे हालात नहीं हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य विकास पथ की ओर अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार में पूरी तरह सामंजस्य है। बिहार का विकास हो रहा है। सुशासन की सरकार है। जनता को न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि राजद का अस्तित्व ही अब समाप्त होने के कगार पर है। बिहार की जनता अब गलती नहीं करेगी। एनडीए पर जनता को पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने भागलपुर में बाढ़ राहत का भी जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों की सुधि ली। इसी दौरान किसी ने मंत्री को सूचना दी गई कि खरीक प्रखंड के चोरहर में कटाव पीड़ितों को भोजन नहीं मिल रहा है। 130 परिवारों के समक्ष आवास सहित भोजन-पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मंत्री ने तत्काल डीएम को बुलाकर चोरहर में सामुदायिक रसोई शुरू कराने का आदेश दिया। इसके पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह ने मंत्री के समक्ष मेरचा, चोरहर, सिंहकुंड के कटाव पीड़ितों व विस्थापितों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोसी के कटाव से विस्थापित तीन गांवों के लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है।

बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री सह भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय बुधवार को नवगछिया पुहंचे जहां उनका अनेकों जगहों पर एनडीए व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया।इस अवसर पर नवगछिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंत्री रामसूरत राय का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के नेतृत्व में अभिनंदन सर पार्टी कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

जिला मंत्री अजित पटेल मुकेश राणा जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बिहुला की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग एवं नवगछिया में पुराने वार्ड नं तीन का सर्वे जल्द कराने की मांगों को रखा। इस मौके पर पूर्व सांसद अनिल यादव ने गोपालपुर अंचल अंतर्गत खास मल कचहरी को रंगरा अंचल में समायोजन का मुद्दा उठाया पूर्व सांसद ने कहा कि गोपालपुर प्रखंड का अधिकतर गांव खास माल में आता है जिसके कारण लोगों को रसीद कटाने से लेकर के सभी तरह की जमीन के कागजात को लेकर के 15 से 20 किलोमीटर घूमकर रंगरा प्रखंड जाना पड़ता है जिससे लोगों को परेशानी होता है प्रखंड गोपालपुर अंचल रंगरा होने से कई तरह के कागजात में भी परेशानी होती है उन्होंने कहा कि अगर इसको गोपालपुर में रहने दिया जाए तो आम लोगों को इसकी सुविधा होगी वही इस मौके पर नवगछिया अंचलाधिकारी एवं अन्य अंचलों के अंचलाधिकारी वो कई राजस्व पदाधिकारी के भी लोगों ने शिकायत किया शहीद पुर निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ गुलाबी जी ने कहा कि सैदपुर गांव में स्थित अंग्रेजों बना उच्च विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गया है जिसे तत्काल वहां पर नए भवन के निर्माण की जरूरत है जिसके उपरांत पठन-पाठन के साथ इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय बनाने की प्रक्रिया हो पाएगा। इस मौके पर मंत्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर जो भी समस्याएं हैं जो भी आवेदन आया है उसे पारदर्शिता के साथ जांच किया जाएगा जहां तक संभव होगा लोगों की समस्या की सुनवाई होगी।

भारतीय पुरुष हाकी टीम के 41 वर्ष बाद पदक जीतने पर सीएम योगी बोले- पांच अगस्त का महत्व और बढ़ा

लखनऊ। ओलंपिक खेलों में 41 वर्ष बाद भातीय पुरुष हॉकी टीम के पदक जीतने पर देश में चारों ओर उल्लास का माहौल है। खेल प्रेमी तथा खिलाड़ियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर को ऐतिहासिक बताया है। सभी ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों तथा प्रबंधन को बधाई दी है। जापान के टोक्यो में चल रहे ओलिंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम का कभी ओलंपिक में लम्बे समय तक दबदबा रहा। इसके बाद तो 1980 के मास्को ओलंपिक के पदक का सूखा गुरुवार को समाप्त हो पाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष से मेडल के सूखे को खत्म करते हुए आज कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक पर कब्जा किया। हॉकी टीम की इस शानदार जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी हॉकी टीम पर गर्व है टीम ने शानदार विजय हासिल कर देश का नाम ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम की इस सफलता पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। आज पांच अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक इतिहास और बन गया। टीम की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हार्दिक बधाई टीम इंडिया।

संक्षिप्त खबर

दस रुपये का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म, कटिहार में विवाहिता का सिर मुंडवा ससुराल वालों ने किया अत्याचार

पटना। बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कटिहार में घटित हुई दो वारदातें इस बात की तस्दीक करती हैं। पहला मामला बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां दस रुपये का लालच देते हुए एक मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तरफ मनसाही थाना क्षेत्र एक विवाहिता का सिर मुंडवा दिया गया।

बरारी थाना क्षेत्र के एक गांव के बहियार मे घास काटने गई एक मासूम को दस रूपये का लालच देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश मे आया है। मामले मे पीड़िता की मां ने बरारी थाना मे केस दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि गांव में जिले के कदवा थाना क्षेत्र के धतुरी चौधरी उर्फ दयानंद चौधरी मजदूरी का काम करता है। सोमवार को लड़की घास काटने खेत गई थी। जहां 10 रुपये देकर बहला फुसलाकर धतुरी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया कार्रवाई जारी है। मनसाही थाना अन्तर्गत किसान चौक हड्डी बथना गांव में पारिवारिक विवाद में पति, सास व ससुर ने मिलकर विवाहिता का सिर मुंडवा दिया। सड़क किनारे जबरदस्ती महिला का बाल काटे जाने का वीडियो बना एक राहगीर ने वायरल कर दिया। जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पति, सास, ससुर व नाई को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक किसान चौक के सुखाडी महतो की पत्नी मीना देवी का उसके पति, सास, ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों ने जबरन सिर मुंडा दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पति सुखाड़ी महतो, ससुर लालू महतो, सास मनकी देवी व सिर मुंडने वाले नाई योगेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला दो बच्चों की मां है। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने विवाहिता के चरित्र पर लांछन लगाते हुए घृणित कार्य को अंजाम दिया।

सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का बड़ा बयान, जातीय जनगणना जरूरी नहीं, गरीबों की हो गणना

गोपालगंज। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इसकी जगह गरीबों की गणना सरकार कराए ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। मंत्री बनने के बाद भाजपा विधायक पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जातपात में लोग जब तक डूबे रहेंगे तबतक देश का विकास नहीं हो सकता।

1931 के बंद क्यों की गई जातीय जनगणना

मंत्री ने कहा कि अगर जातीय जनगणना हुई तो किसी खास वर्ग को इससे फायदा होगा लेकिन समाज को समग्र रूप से इससे हानि होगी। अगर जातीय जनगणना से लाभ होता तो फिर 1931 के बाद इसे बंद क्यों कर दिया गया। इसका बुरा असर दिखने के कारण ही तो इसे बंद कर दिया गया था। इससे तनाव की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी गणना की जाए। हमें किसी जाति को नहीं बल्कि गरीबों को उपर उठाना है।

इससे पूर्व गोपालगंज के जिला भाजपा कार्यालय में मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान व चिंता करती है। आज देश व राज्य की एनडीए सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। जैसे कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे ही पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता व सम्मान का ख्याल रखती है। मंत्री सुभाष सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैकुंठपुर प्रखंड के राजा पट्टी, माझा के दानापुर व शहर के अरार मोड़ पर भव्य स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, निवर्तमान विधान पार्षद आदित्य नारायण पाण्डेय, जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने मंत्री का स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में आने का मौका मिला है। जिले में चार दिन तक रहेंगे। इस दौरान लोगों की समस्या सुनकर उसका निदान किया जाएगा।

जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दो टूक कहा, संगठन से उपर कोई नहीं, मिशन 2024 व 2025 में जुटे कार्यकर्ता

गया। जदयू कार्यकर्ता संवाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। कहा कि संगठन के लिए काम करने वालों को तरजीह दी जाएगी। चाहे वह पंचायत में काम कर रहा कोई आम कार्यकर्ता ही क्यों न हो। संगठन से उपर कोई नहीं होता। कार्यक्रम का आयोजन धर्मसभा भवन सभागार में बुधवार को किया गया था।

उन्होंन जदयू के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिशन 2024 लोकसभा चुनाव व 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही जुट जाने को कहा। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों, पदाधिकारियों से कहा कि जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद के नेतृत्व में समन्वय बनाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। पिछले चुनाव में महत्वपूर्ण सीटों पर मिली हार के बाबत कहा कि आपसी एकजुटता से हम सभी 45 सीट से 145 पर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरेक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व नेता के काम का आकलन किया जा रहा है। आपका काम ही रिपोर्ट कार्ड तय करेगा।

पार्टी नेताओं द्वारा प्रखंड व पंचायत स्तर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा तबज्जों नहीं दिए जाने को लेकर कहा कि पार्टी के सक्रिय नेता व कार्यकर्ता की शक्ति और उनके अधिकार बढ़ाए जाएंगे। प्रखंडों में 20 सूत्री और सशक्त होगी। तमाम सरकारी योजनाओं में अनुश्रवण समिति बनेगी। वहां पार्टी के नेता व कार्यकर्ता आम जनों के लिए काम करेंगे।

तीन वर्ष में पुलिस विभाग में अधिकतम आवास बनेंगे

गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिसकर्मियों के लिए बने 1556 आवासों का किया वर्चुअल लोकार्पण

भोपाल (एजेंसी)। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस के निश्चिंतता पूर्वक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आवश्यक इंतजाम के सकल प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी तीन वर्षों में पुलिस विभाग में अधिकतम आवासों के निर्माण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आठ जिलों में 304 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नव-निर्मित 1556 आवासों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी तीन वर्षों में पुलिस विभाग में अधिकतम आवासों के निर्माण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।

आठ शहरों में 13 स्थानों पर हुआ लोकार्पण

अध्यक्ष, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन विजय यादव ने बताया कि राज्य-स्तर से 304 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1556 आवास-गृह लोकार्पित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक ग्वालियर के 576 और सीधी तथा बुरहानपुर में 68-68 आवास शामिल हैं। रीवा में 256, सागर में 180, जबलपुर में 152 और छतरपुर तथा धार के 128-128 आवास लोकार्पित किए गए हैं। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस आवासों के लोकार्पण अवसर पर विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मियों से वर्चुअली संवाद किया।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि विभाग के कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए जरूरी है कि अधिकारी-कर्मचारियों को बेहतर संसाधन के साथ उपयुक्त वातावरण भी मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संकट में भी पुलिस विभाग ने पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य किया। हमारे जवानों को शहादत भी देनी पड़ी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या से निश्चिंतता के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। विगत 40 वर्षों से पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रतिवर्ष औसतन 800 क्वार्टर्स का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 2,384 पुलिस आवास-गृहों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि आवासों के लोकार्पण की श्रृंखला में शुक्रवार 06 अगस्त को इंदौर में भी 818 पुलिस आवास-गृहों का लोकार्पण किया जाएगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज से इंदौर के दो दिवसीय दौरे पर

भोपाल (एजेंसी)। गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा 6 एवं 7 अगस्त को इंदौर के दौरे पर रहेंगे। डॉ. मिश्रा 6 अगस्त को सुबह 10.30 बजे कार से भोपाल से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। वे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन उपरांत सायंकाल 4.00 बजे इंदौर पहुंचेंगे।

डॉ. मिश्रा शाम 5.00 बजे इंदौर में 15वीं बटालियन कैंपस स्थित नव-निर्मित पुलिस आवास-गृहों का लोकार्पण करेंगे। डॉ. मिश्रा कलेक्ट्रेट, इंदौर में शाम 5.30 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निः शुल्क राशन वितरण योजना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके पश्चात डॉ. मिश्रा स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉ. मिश्रा सात अगस्त को सुबह 8.00 बजे रेसीडेंसी सर्किट हाउस में आमजन से भेंट करेंगे।

डॉ. मिश्रा सुबह 10 बजे इंदौर के मूसाखेड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निःशुल्क अन्न वितरण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री डॉ. मिश्रा हातोद में चार करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि-पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

सीएम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के कारण नहीं हो सकी कैबिनेट

अब आज होगी कैबिनेट की बैठक

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहने के कारण कैबिनेट नहीं हो सकी। अब यह कैबिनेट शुक्रवार को सुबह 11.00 बजे से होगी।

मुख्यमंत्री बुधवार रात्रि को ही दिल्ली से लौटे थे। दिल्ली में मप्र के सांसदों की बैठक में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर बुधवार को मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में बमुश्किल 20 मिनट रुकने के बाद मप्र में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए और वहां उनका होना ज्यादा जरूरी बताते हुए जेपी नड्डा से अनुमति लेकर वे भोपाल के लिए रवाना हो गए थे। यहां बुधवार रात में ही वापसी के बाद उन्होंने आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री निवास में बैठक की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जरूरी निर्देश दिए। गुरुवार सबेरे भी वे लगातार व्यस्त रहे।

सुबह मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ ही कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बाद में वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकल गए। इस कारण बुधवार दोपहर में होने वाली कैबिनेट स्थगित कर दी गई। अब यह कैबिनेट शुक्रवार को होगी। कैबिनेट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि देने के बारे में आरबीसी 6-4 में संशोधन करने सहित मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी जा सकती है।

मूंग खरीदी के लिए प्रतिदिन 50 किसानों को भेजें एसएमएस : पटेल

भोपाल । किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने संचालक कृषि को निर्देशित किया है कि मूंग खरीदी के लिए प्रतिदिन 50 किसानों को एसएमएस भेजे जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मंत्रालय में मूंग खरीदी की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने संचालक कृषि श्रीमती प्रीती मैथिल एवं अन्य कृषि अधिकारियो की बैठक लेकर मूंग खरीदी के लिए प्रतिदिन 35 छोटे किसानो को और 15 बड़े किसानों को मैसेज भेजे जाने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने निर्देशित किया कि पोर्टल में सुधार के समय पोर्टल बंद रहने के दौरान जिन किसानों को मैसेज भेजे गए थे, उन किसानों को पुनः मेसेज भेजे जाएं। बैठक में उन्होंने बताया कि मेसेज की अवधि दिनांक 09 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत मंत्री ने लिखित में दिया आश्वासन

पंचायत कर्मचारियों पर की गई निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई वापस होगी

भोपाल (एजेंसी)। पूरे मध्यप्रदेश में सर्वहारा वर्ग की योजनाओं को प्रभावित करने के बाद अर्थव्यवस्था चौपट कर चुके हड़ताली पंचायत कर्मचारियों को सरकार ने गुरुवार को संतुष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत मंत्री द्वारा बुलाई गई वार्ता में हड़ताली पंचायत कर्मचारियों को लिखित में आश्वस्त किया गया कि उन पर की गई बर्खास्तगी, निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई वापस होगी। यह भी आश्वासन दिया गया कि जो भी मांगें हैं, 15 अगस्त के बाद अगली बैठक में उन पर सहमति बन जाएगी।

विगत 22 जुलाई से बेमुद्दत कलम बंद हड़ताल कर रहे पंचायत विभाग के इंजीनियर, सचिव, रोजगार सहायक, वाटर सेट सेवक, मनरेगा के संविदा उपयंत्री सहित अन्य कर्मचारियों की संयुक्त हड़ताल ने शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में पूरी व्यवस्था चौपट कर डाली। गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा योजना में जहां काम का दायरा घटा है तो पंचायतों से अनुशंसित होने वाली जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का काम भी बिखर सा गया है। पिछले 15 दिनों से अनवरत होकर आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों को वापस काम पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को वार्ता करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हालांकि पंचायत कर्मचारी विभाग के मंत्री की बजाए गृह मंत्री से चर्चा करना चाह रहे थे। कारण भी है कि पिछली दो बार वार्ताओं में पंचायत मंत्री मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं दे पाए थे, लेकिन गृहमंत्री ने दो टूक कह दिया कि मुख्यमंत्री का अगर उन्हें निर्देश मिलेगा तभी वह पंचायत कर्मचारियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री के निर्देश मिले कि पंचायत मंत्री आज किसी भी हाल में कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवाएंगे। पहले विभाग के मंत्री लिखित में आश्वासन देने को तैयार नहीं थे, लेकिन सभी कर्मचारी उनके बंगले पर अड़ गए तो गुरुवार शाम सात बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चर्चा चली। इसके बाद मंत्री ने लिखित में सहमति दी की हड़ताली कर्मियों पर निलंबन, बर्खास्तगी एवं एफआईआर की कार्रवाई वापस होगी। इसके लिए मंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिव को भी मौके पर निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी हड़ताल की अवधि का वेतन भी नहीं काटा जाएगा।

मांगों का समुचित समाधान कराने के लिए 15 अगस्त के बाद अगली बैठक

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मोर्चा के संयोजक दिनेश शर्मा, सह संयोजक रोशन सिंह परमार के अलावा घटक सदस्य डीके उपाध्याय, लीलाधर अहिरवार और शैलेंद्र चौकसे सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचायत मंत्री ने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनांक से गणना रोजगार सहायक संविदा इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर 15 अगस्त के बाद बैठक होगी। मोर्चा के संयोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि हड़ताल अभी स्थगित की गई है समाप्त नहीं हुई है। अगर 15 अगस्त के बाद सभी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे। मोर्चा के संयोजक एवं सहसंयोजक ने बताया कि लिखित में सहमति के बाद यह हड़ताल स्थगित हुई है।

संक्षिप्त समाचार

वन मंत्री ने अत्याधुनिक एम्बुलेंस को झण्डी दिखाकर किया रवाना

भोपाल । वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक एम्बुलेंस में सभी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनसे गंभीर मरीजों को तुरंत चिकित्सकीय सेवाएँ उपलब्ध होगी, जिनसे अल्प समय में अस्पताल में इलाज हो सकेगा। वन मंत्री सीएसआर फंड के अंतर्गत अत्याधुनिक तीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। वन मंत्री डॉ. शाह के अथक प्रयासों से हरसूद विधानसभा क्षेत्र के खालवा और हरसूद क्षेत्र के लिये एलएनटी कम्पनी, भोपाल ने एक करोड़ 20 लाख की लागत से तीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं। वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इन एम्बुलेंसों में दो ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर मशीन की व्यवस्था की जायेगी। एक मशीन के खराब होने पर तात्कालिक रूप से दूसरी का उपयोग किया जा सकेगा।

कमलनाथ कल करेंगे ग्वालियर और चंबल अंचल का दौरा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने गुरुवार को यहां बताया कि श्री कमलनाथ सात अगस्त को सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे। वे ग्वालियर से दतिया जाएंगे और वहां जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों से मुलाकात करेंगे। श्री सलूजा ने बताया कि श्री कमलनाथ इसके बाद शिवपुरी में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मुलाकात करेंगे। श्री कमलनाथ शिवपुरी के बाद श्योपुर जिला मुख्यालय भी जाएंगे। इसके बाद श्री कमलनाथ ग्वालियर लौटेंगे।

भारतीय हॉकी टीम की जीत ने बढ़ाया देश का मान : शर्मा

भोपाल । ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस जीत से भारतीय हॉकी टीम ने देश का मान बढ़ाया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों की ओर से भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि ओलंपिक में 41 साल बाद मैडल लाकर हमारी हॉकी टीम युवाओं को प्रेरित किया है। आज इस जीत से भारतीय हॉकी के वर्चस्व को पुनः विश्व स्तर पर स्थापित करने की शुरुआत हुई है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी पुरुष हॉकी टीम ने इस शानदार जीत से देश का मान बढ़ाया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने गुरुवार को ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल में वेक्सीन का दूसरा डोज लगवाया।

आदिवासी दिवस पर स्थानीय अवकाश को लेकर दुविधा में कलेक्टर

मंडला कलेक्टर ने पहले स्थानीय अवकाश का आदेश जारी किया, फिर वापस लिया

भोपाल (प्रसं)। मप्र में 09 अगस्त को आदिवासी दिवस पर स्थानीय अवकाश घोषित करने को लेकर आदिवासी बहुल जिले के कलेक्टर दुविधा में फंस गए हैं। कुछ इसी तरह का मामला मंडला में सामने आया है।

यहां कलेक्टर ने पूर्व में एक आदेश जारी कर दीपावली भाई दूज के दिन के लिए 06 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया था। इसे निरस्त कर 09 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया था। यह आदेश 5 अगस्त को ही जारी किया गया था, लेकिन बाद में एक और आदेश जारी कर विश्व आदिवासी दिवस पर 09 अगस्त को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया है। हालांकि अन्य आदिवासी बहुल जिलों के कलेक्टरों ने अभी इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन वे राज्य सरकार से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। अभी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस कारण उनकी दुविधा बरकरार है। इधर प्रदेश के आदिवासी संगठनों ने स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए कलेक्टरों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस कारण फिलहाल इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

यहां नेतागिरी मत करो, वह तो हम विधानसभा में कर लेंगे

ग्वालियर, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को ग्वालियर आए और उन्होंने डबरा भितरवार क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। लेकिन क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक ने समर्थकों के साथ यहां एक गांव में धरना दिया और विरोध करने का प्रयास किया तो सीएम ने माइक पर कांग्रेस विधायक से कहा कि नेतागिरी मत करो, नेतागिरी तो विधानसभा में कर लेंगे।

सीएम चौहान ने कांग्रेस विधायक को दी नसीहत

मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को जिले के डबरा और भितरवार के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम जब भितरवार क्षेत्र में गए तो हरसी रोड पर पलायछा गांव के बाहर भितरवार के कांग्रेस विधायक लाखन सिंह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के काफिला का रास्ता रोकने का प्रयास करने लगे। कांग्रेस विधायक की मांग थी कि प्रभावितों को दो दिन में मुआवजा मिले और तत्काल राशन की व्यवस्था की जाए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मुख्यमंत्री के लिए रास्ता बनाया। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान, कांग्रेस विधायक लाखन सिंह को लेकर फॉलो गाड़ी पर चढ़ गए और जनता को संबोधित करने लगे। इसी बीच कांग्रेस विधायक ने कुछ कहने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें टोकते हुए कहा नेतागिरी मत करो, नेतागीरी तो हम विधानसभा में कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता से कहा चिंता नहीं करो नुकसान का आंकलन हो रहा है। सरकार को सबकी फिक्र है।

मंगू की खरीद का कोटा बढ़ाया जाए : कमलनाथ

भोपाल । प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा मूंग की खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ नें बेहद कम बताते हुए इसके कोटे में बढ़ोत्तरी की मांग केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। नाथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि मध्यप्रदेश में खुद सरकार के मुताबिक ग्रीष्मकालीन मूंग का 3,16,892 किसानों द्वारा 8.36 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया है, जिस का उत्पादन 12.12 लाख मीट्रिक टन होता है। पूर्व में प्रदेश को 1.34 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य मिला था, जिसे अब 1.13 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाकर 2.47 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जो कि बेहद कम है। प्रदेश में मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है। आज किसान अपनी मूंग को बेचने के लिए परेशान हो रहा है। शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी इसके बंपर उत्पादन के आधार पर इसके कोटा को बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था, लेकिन जो कोटा बढ़ाया गया है वो अपर्याप्त है। मैं केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह करता हूं कि किसान हित में इस कोटे को और बढ़ाया जाए ताकि अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए परेशान हो रहे किसान को राहत मिल सके।

अर्चना जायसवाल ने कहा, जनता के सामने खोलेंगे जनविरोधी भाजपा सरकार की पोल

महिलाओं के हक के लिए सड़कों पर उतरेगी महिला कांग्रेस

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश की महिलाओं के हक, बढ़ती महंगाई एवं कोराना से मृत परिवार की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेंगी और हरसंभव मदद का आश्वासन दिलाएगी। यह बात प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

डॉ. जायसवाल ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब प्रदेश में महिला अपराध, बलात्कार की घटनाएं नहीं हों फिर भी प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर किंचित मात्र भी गंभीर नहीं है। बढ़ती महंगाई को लेकर डॉ. जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश की असंवेदनशील भाजपा सरकार आम जनता को राहत देने की बजाय सरकार जनता पर टेक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है। आज पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस और खाद्य सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। गरीबों को बिजली के अनाप-शनाप बढ़े हुए बिल थमाए जा रहे हैं। शराब माफियाओं का जिक्र करते हुए डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार शराब माफियाओं पर सख्त कार्यवाही कर उन पर रासुका लगाए। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर भी शीघ्र आएंगे, आंदोलन भी करेंगे, डंडे भी खाएंगे व जेल भी जाएंगे और जनविरोधी भाजपा सरकार की पोल खोलकर जनता केसामने उजागर करेंगे।

डॉ. जायसवाल ने कहा कि महिला कांग्रेस आगामी उपचुनावों, नगरीय निकाय चुनावों व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी महिला कांग्रेस एक सक्षम व जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मिशन 2023 के तहत कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य में अपनी जुझारू महिला कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी और प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सौजन्य मुलाकात की।

उच्च शिक्षा विभाग में विवि सेवा के अधिकारियों का टोटा, शिक्षक संवर्ग को बनाया कुलसचिव

भोपाल (एजेंसी)। उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों को टोटा हो गया है, जिसकी वजह से विभाग को कॉलेज के प्राध्यापक और सह प्राध्यापक को विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर पदस्थ करना पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे का कारण विवि सेवा में कई सालों से भर्ती नहीं होना बताया जाता है।

राज्य शासन ने उच्च शिक्षा के विवि सेवा के अधिकारियों एवं विभिन्न प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विभिन्न विवि में पदस्थ किया है। जारी आदेश में डॉ. बृजेश सिंह प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, कॉलेज सतना को कुलसचिव, रानी दुर्गावती विवि जबलपुर और दिलीप सोनी सह प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, माधव विज्ञान कॉलेज उज्जैन को कुलसचिव, महर्षि पाणिनी संस्कृत एंव वैदिक विवि प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है,जबकि यह कुलसचिव का पद उच्च शिक्षा विभाग विवि सेवा के अधिकारियों का है। कुछ साल पहले उच्च शिक्षा ने नियम में बदलाव कर कॉलेज प्राध्यापक को विवि कुलसचिव पद पर पदस्थ करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत कर दिया था। गुरुवार को किए गए तबादलों में अनिल शर्मा उप कुलसचिव, देवी अहिल्या विवि इंदौर को कुलसचिव बरकतउल्ला विवि भोपाल और अनित राय सहायक कुलसचिव, बरकतउल्ला विवि भोपाल को ओएसडी उच्च शिक्षा मंत्रालय भोपाल पदस्थ किया है।

अनित राय ओएसडी उच्च शिक्षा और अनिल शर्मा बीयू कुलसचिव बनाए गए

अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थपना	नवीन पदस्थापना
अनिल शर्मा	उप कुलसचिव, देवी अहिल्या विवि इंदौर	कुलसचिव, बीयू विवि भोपाल
डॉ. वृजेश सिंह	प्राध्यापक, भोतिक शास्त्र, कॉलेज सतना	कुलसचिव, रादुवि जबलपुर
दिलीप सोनी	सह प्राध्यापक, एमवी कॉलेज उज्जैन	कुलसचिव, संस्कृत एंव वैदिक विवि, उज्जैन
मेघराज निनामा	उप-कुलसचिव, विक्रम विवि उज्जैन	उप-कुलसचिव, बुंदेलखंड विवि, छतरपुर
सुषमा सैयाम	उप कुलसचिव, बुंदेलखंड विवि, छतरपुर	उप-कुलसचिव, विक्रम विवि उज्जैन
अनित राय	सहा. कुलसचिव, बीयू विवि भोपाल	ओएसडी उच्च शिक्षा, मंत्रालय
अभय गुप्ता	सहा. कुलसचिव, भोज मुक्त विवि भोपाल	सहा. कुलसचिव, बीयू विवि भोपाल
नितिन सांगले	सहा. कुलसचिव,निजी विवि वि. आ.भोपाल	सहायक कुलसचिव, रादुवि जबलपुर

भारत की विशेष

एथलीट टीम को लीड करेंगे सोनू

कोरोनाकाल में जरूरतमंदों की मदद करके बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। वही अब सोनू सूद के फैंस के लिए खुशखबरी है। एक्टर को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। सोनू सूद अगले साल रूस में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के दल का हिस्सा भी रहेंगे। खबरों के अनुसार इस बात की घोषणा हाल ही में सोनू सूद ने भारत के खास एथलीटों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की है। सोनू सूद ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे विशेष ओलंपिक भारत के साथ शामिल होने की इस यात्रा में शामिल होने की खुशी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सोनू ने सभी स्पेशल एथलीट से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही उन्होंने उनके अचीवमेंट्स की सराहना भी की। ओलंपिक शीतकालीन खेल संस्करण अगले साले 22 से 28 जनवरी तक रूस के कजान में आयोजित किया जाएगा।

कैटी ने अपने ग्लैमरस लुक से फैंस को किया हैरान

अमेरिकी गायिका कैटी पेरी ने इटली के कैपरी में यूनिसेफ के एक कार्यक्रम के दौरान अपने स्टाइलिश लुक से अपने प्रशंसकों को चकित कर दिया। फोटो में वे फ्लोर-लेंथ स्ट्रैपलेस ब्लैक गाउन पहने दिखाई दे रही है जिसके साथ उन्होंने सिल्वर इयररिंग्स और स्टनिंग अपडो हेयरस्टाइल कैरी की है। जैसे ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट की, कमेंट के आने शुरू हो गए। प्रशंसकों ने कार्यक्रम में उसकी उपस्थिति को पसंद किया और कमेंट में वाह, लव यू और ऑसम लिखा। उसने फोटो को दिल के आइकन के साथ कैप्शन दिया, लुइसा वियारोमा और निश्चित रूप से मेरे दोस्त यूनिफिटेलिया को मेरा प्यार।

अनु मलिक पर लगा इजराइल के राष्ट्रगान की धुन चुराने का आरोप

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक अक्सर किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। वही अब अनु मलिक टोक्यो ओलंपिक में इजराइल के जिमनास्ट डोल्गोपयात के गोल्ड मेडल जीतने के बाद ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, डोल्गोपयात की जीत के बाद देश का नेशनल एंथम बजा, जिसे सुनने के बाद लोग अनु मलिक पर इसकी धुन चुराने का आरोप लग रहा है। इजरायल के नेशनल एंथम को सुनते ही लोगों को मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन की याद आ गई। जिसे लेकर यूजर्स ने अनु मलिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि क्या उन्हें कॉपी करने के लिए दूसरे देश का एंथम सॉन्ग ही मिला। यूजर्स का कहना है कि अनु मलिक ने इसराइल के राष्ट्रगान की धुन कॉपी करके 1996 में ? रिलीज हुई फिल्म दिलजले के गाने मेरा मुल्क मेरा देश है बनाया था। इससे पहले भी अनु मलिक पर धुन कॉपी करने का आरोप लग चुका है। बीते दिनों अनु मलिक मीटू मूवमेंट के दौरान भी काफी लाइमलाइट में आ गए थे। इस वजह से उन्हें इंडियन आइडल की जज की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि अब एक बार फिर वह इंडियन आइडल में नजर आ रहे हैं।

जाह्नवी ने बताया अपना ड्रीम वेडिंग प्लान

फिल्म धड़क से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जाह्नवी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। वही अब जाह्नवी के अपने वेडिंग प्लान का खुलासा किया है। हाल ही में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर ने अपना पूरा वेडिंग प्लान बताया है। जाह्नवी ने बैचलरेट पार्टी से लेकर शादी तक की पूरी तैयारी की हुई है। जाह्नवी का कहना है कि वह सिंपल और प्यारी शादी चाहती हैं जो 2 दिन में हो जाए। जाह्नवी कपूर ने कहा, मेरी बैचलरेट पार्टी कैप्री मे याच में हो और शादी तिरुपति में। मेहंदी और संगीत सेरेमनी मयलापुर में हो। उन्होंने कहा कि रिसेप्शन को लेकर मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। रिसेप्शन जरूरी होता है क्या? नहीं न तो छोड़िए रिसेप्शन। शादी की डेकोरेशन को लेकर एक्ट्रेस ने कहा, शादी की डेकोरेशन ट्रेडिशनल लेकिन सिंपल होगा। मोगरा और मोमबत्तियों से डेकोरेशन होनी चाहिए और 2 दिन में पूरी शादी हो जाए। मेरी शादी में खुशी और अंशुला कपूर ब्राइड्समेड्स होगी। शादी में खुशी और पापा इमोशनल हो जाएंगे तो ऐसे में अंशुला दीदी सब संभाल सकती हैं। अपनी वेडिंग आउटफिट को लेकर जाह्नवी ने कहा, मैं कांजीवरम या पट्टू पावड़ाई साड़ी पहनूंगी और वो गोल्ड की होगी। मेहंदी आउटफिट पिंक कलर का होगा और संगीत का आउटफिट येलो कलर का। मेरा पति समझदार होना चाहिए क्योंकि मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली हूं।

अभिनेत्री वाणी का चौंकाने वाला खुलासा

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' के बाद से ही हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनी रहीं खूबसूरत अभिनेत्री वाणी कपूर अपनी अगली फिल्म 'बेलबॉटम' को लेकर खासी उत्साहित हैं। फिल्म में वह अक्षय कुमार के साथ काम कर रही हैं। लेकिन उनके किरदार को लेकर अब ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फिल्म में उनका किरदार छोटा सा है हालांकि ये है बहुत प्रभावशाली। वाणी बताती हैं कि इस फिल्म के लिए उन्होंने ऑफर मिलते ही तुरंत हां इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें फिल्म में अक्षय के साथ कैमरे के सामने आने का मौका मिल रहा था। वाणी कहती हैं, मुझे अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और मैं उनके इस विश्वास व भरोसे के लिए उनकी आभारी हूं। हां, ये सच है कि फिल्म 'बेलबॉटम' में मेरा किरदार छोटा है लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। इस फिल्म को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। फिल्म में मैं अक्षय कुमार के साथ हूं और उनके साथ स्क्रीन साझा करने के लिए मैंने बिना सोचे फिल्म 'बेलबॉटम' में काम करने के लिए हां कह दी थी। वाणी ने एक रहस्य की बात यह भी बताई कि उनके पिता शिव कपूर फिल्म 'बेलबॉटम' के हीरो अक्षय कुमार के प्रशंसक रहे हैं और ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिली थी कि उन्हें अक्षय के साथ काम करने का प्रस्ताव मिला है। वह कहती हैं, डैड को इतना खुश मैंने कम ही देखा है। वह इतने खुश इसलिए थे कि मैं उस स्टार के साथ काम करूंगी जिनकी फिल्में वह लंबे समय से पसंद करते आए थे। जब मैंने उन्हें यह खबर सुनाई, तो वो सातवें आसमान पर थे। फिल्म 'बेलबॉटम' के अलावा वाणी जल्द ही आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' और रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'शमशेरा' में दिखाई देंगी।

मनोज को मिला था हॉलीवुड ऑफर

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में खुलासा किया कि वह अपनी नैशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म पिंजर के बाद हॉलीवुड डेब्यू करने वाले थे। मनोज को एक इंटरनैशनल फिल्म मिली थी जिसमें उनके साथ लिन कॉलिन्स भी थीं। यह 2000 की बात है लेकिन बात नहीं बन सकी। मनोज ने बताया कि वह इंटरनैशनल फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किए गए थे। हालांकि उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में एक योतिषी ने जो बताया था वह एकदम सही साबित हुआ।

-प्रोजेक्ट पर की थी भविष्यवाणी

मनोज ने बताया कि वह एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर गए थे। वहां जाने-माने ऐक्टर श्रीवल्लभ व्यास के पिता से मिले जो कि एक जाने-माने योतिषी थे। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नहीं है। मनोज ने द बॉलीवुड फिल्म क्लब के साथ एक क्लबहाउस सेशन के दौरान ये बात कही।

NRI था फिल्म का डायरेक्टर

मनोज ने बताया, मुझे पिंजर के लिए सेकेंड नैशनल अवॉर्ड मिलना था और इसके बाद जैसलमेर जाना था। मेरे नैशनल अवॉर्ड फंक्शन के बाद मैं जैसलमेर गया। वहां मुझे एक प्रॉपर हॉलीवुड फिल्म करनी थी जिसे एक NRI डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे। मैं लीड रोल में था और लिन कॉलिन्स मेरे साथ फीमेल लीड थीं। सबको लग रहा था कि इस फिल्म के बाद मेरी जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है।

मुझे खाने के लिए यात्रा करना पसंद है-लक्ष्मी मांचू

तेलुगु अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू तेलुगु कुकरी शो अहा भोजनंबु की

मेजबानी के हर पल का आनंद ले रही हैं। वह खुद भी खाने की शौकीन हैं। लक्ष्मी ने बताया, मुझे खाना पसंद है और मेरा कोई पसंदीदा आइटम नहीं है। मुझे थाई, वियतनामी, चाइनीज, इटेलियन सब पसंद है। मुझे भोजन के लिए यात्रा करना पसंद है। मैंने कभी-कभी भोजन के लिए यात्रा की है, खाने में मुझे अलग-अलग स्वाद, और तरीके पसंद हैं। हालांकि मैं अभी फ्रेंच व्यंजनों की आदी हो रही हूं। आठ-भाग की श्रृंखला एक दिलचस्प मोड़ पर है। लक्ष्मी ने एक सेलिब्रिटी अतिथि को आमंत्रित किया है, जिन्हें शो में जो भी सामग्री प्रदान की जाती है, उसके साथ खाना बनाना होता है। कुकरी शो की मेजबानी के बारे में बात करते हुए, लक्ष्मी कहती हैं, मेरी बेटी (निर्वाण) और मैं कुकिंग शो के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मुझे ऑस्ट्रेलियाई टॉप शेफ और अन्य कुकिंग शो देखना बहुत पसंद है। एक शो की मेजबानी करने में सक्षम होने के नाते हमारे नियमित रूप से एक ट्विस्ट के साथ भोजन बहुत रोमांचक बनते है।

कृति का कहना है कि अचानक वजन घटाना-बढ़ाना स्वास्थ्यवर्धक चीज

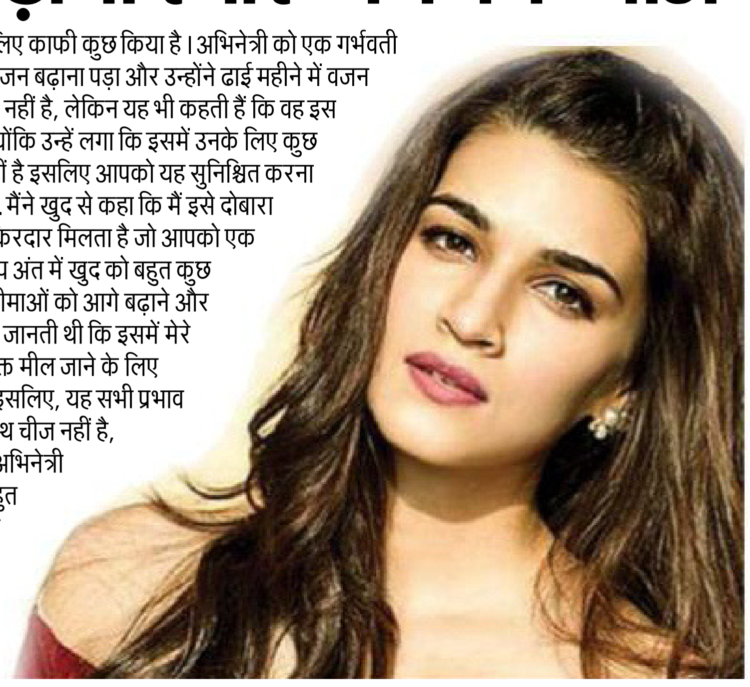

कृति सैनन ने फिल्म मिमी में अपने लुक को निखारने के लिए काफी कुछ किया है। अभिनेत्री को एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाने के लिए कुछ अतिरिक्त किलो वजन बढ़ाना पड़ा और उन्होंने ढाई महीने में वजन बढ़ाया है। वह इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करना स्वस्थ नहीं है, लेकिन यह भी कहती हैं कि वह इस किरदार के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाना चाहती थीं क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें उनके लिए कुछ है। कृति ने बताया कि, जाहिर है, यह बहुत स्वस्थ बात नहीं है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा .. मैं एक चरित्र के लिए बार-बार ऐसा नहीं करूंगी .. मैंने खुद से कहा कि मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी लेकिन मुझे लगता है जब आपको एक ऐसा किरदार मिलता है जो आपको एक अभिनेता के रूप में करने के लिए बहुत कुछ देता है तो आप अंत में खुद को बहुत कुछ वापस दे देते हैं। 31 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि वह उन सीमाओं को आगे बढ़ाने और बाहर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि, मैं हमेशा से जानती थी कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ है इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार थी और इसने स्क्रीन पर बहुत बड़ा बदलाव किया। इसलिए, यह सभी प्रभाव डालता है। शारीरिक रूप से, यह करने के लिए बहुत स्वस्थ चीज नहीं है, खासकर क्योंकि मैंने दो, ढाई महीनों में वजन बढ़ाया है। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उनका वजन बढ़ना और कम होना बहुत स्वाभाविक था। कृति ने कहा मुझे इसे खोने के लिए अपना समय मिला .. मैंने यह सब बहुत स्वाभाविक रूप से किया .. लेकिन हां, एक अभिनेता के रूप में आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे इन परिवर्तनों से अक्सर नहीं ले रहे हैं।

हॉकी में पदक का सूखा खत्म

चार दशक बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक कांस्य पदक

टोक्यो (एजेंसी)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहां गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हरा कर 41 वर्षों बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीत कर पदक का सूखा खत्म किया। 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों के बाद यह भारत का पहला ओलंपिक हॉकी पदक है। वहीं यह ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। अन्य दो कांस्य पदक 1968 मेक्सिको सिटी और 1972 म्यूनिख खेलों में आए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओवरऑल ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें आठ स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। मैच की बात करें तो दोनों टीमों ने अपनी ताकत के साथ हॉकी खेली। जर्मनी शुरुआत में भारत के मुकाबले थोड़ा हावी रहा। दूसरे मिनट में पहला गोल भी जर्मनी की तरफ से ही हुआ। मिडफील्डर ओरुज तिमूर ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके बाद भारत ने एक गोल की तलाश में आक्रामकता दिखाई, लेकिन गोल नहीं हो पाया और पहला क्वार्टर 1-0 के स्कोर पर समाप्त हुआ।

सिमरनजीत सिंह ने किया पहला गोल

दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही भारत को वो गोल मिला, जिसकी उसे तलाश थी। फॉरवर्ड सिमरनजीत सिंह ने 17वें मिनट में शानदार गोल दाग कर टीम को बेहद जरूरी 1-1 की बराबरी कराई, हालांकि इसके बाद जर्मनी ने एक-एक मिनट के अंतराल में दो गोल करके अपनी बढ़त को 3-1 कर लिया। फॉरवर्ड वेलेन निकलस और फुर्क बेनेडिक्ट ने क्रमशः 24वें और 25वें मिनट में ये गोल दागे। 3-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तेजी दिखाई, जिसका अच्छा परिणाम मिला। भारत 27वें और 29वें मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हुआ। मिडफील्डर हार्दिक सिंह और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह ने इन मौकों को भुनाया और गोल करके टीम को 3-3 से बराबरी कराई। इसी के साथ दूसरा क्वार्टर समाप्त हुआ।

तीसरे क्वार्टर में दागे दो गोल

इसके बाद मैच में भारत ने पकड़ बनाए रखी। दूसरे क्वार्टर में मिली लय को बरकरार रखते हुए टीम ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही दो गोल दागे और 5-3 की मजबूत बढ़त ले ली। 31वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी डिफेंडर रुपिंदर पाल सिंह ने गोल में तब्दील किया। इसके ठीक तीन मिनट बाद 34वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने फिर अपना जलवा दिखाया और एक शानदार गोल किया। गोल के साथ-साथ भारत ने डिफेंस में भी अच्छा काम किया।

गोलपोस्ट पर बैठकर जीत का जश्न मनाते मैच के हीरो गोलकीपर श्रीजेश

श्रीजेश का पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल

आखिरी के 6 सेकंड में पेनाल्टी रोककर दिलाया मेडल

35 साल के श्रीजेश ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है। खासकर मैच के आखिरी के 6 सेकंड में उन्होंने जिस तरह पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील होने से बचाया उसके बाद उन्हें हॉकी की दीवार कहा जा रहा है। गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मौकों को गोल में तब्दील होने से बचाया। उन्होंने 9 बार गेंद को गोल पोस्ट में जाने से रोका। मैच जीतने के बाद श्रीजेश गोलपोस्ट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने वह जवाब दिया जो आमतौर पर हर एक गोलकीपर देता। श्रीजेश ने कहा, मेरे लिए गोलपोस्ट ही सबकुछ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गोलपोस्ट पर ही बिताई है। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि इस गोलपोस्ट का ओनर मैं हूं। श्रीजेश ने कहा, मैं आज हर चीज के लिए तैयार था। यह 60 मिनट सबसे अहम थे। मैं 21 साल से हॉकी खेल रहा हूं और मैंने खुद से इतना ही कहा कि 21 साल का अनुभव इस 60 मिनट में झोंक दो। आखिरी पेनल्टी पर उन्होंने कहा, मैंने खुद से इतना ही कहा कि तुम 21 साल से खेल रहे हो और अभी तुम्हे यही करना है। एक पेनल्टी बचानी है। पूरे ओलंपिक के दौरान इस दीवार ने कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाई। मैच के बाद उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ उन्हें फोन किया। मैं उन्हें बताना चाहता था कि हमने पदक जीत लिया है और मेरा पदक उनके लिए है।

सचिन ने कहा, आखिरी पलों में श्रीजेश का सेव अद्भुत

भारतीय क्रिकेट स्टार सचिन बोले, आखिरी पलों में श्रीजेश का सेव अद्भुत। सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारत के लिए ब्रॉन्ज जीतने पर हॉकी टीम के हर सदस्य को बधाई। ये बहुत कड़े मुकाबले से मिली जीत है। आखिरी पलों में श्रीजेश ने जो पेनल्टी कॉर्नर बचाया, गेम का वो पल शानदार था। पूरा देश बहुत गौरवान्वित है। गंभीर ने कहा, हॉकी का मेडल किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बड़ा है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, चक दे फट्टे।

विवेक के गांव में जश्न का माहौल

भोपाल। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को पराजित कर कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर के मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित गृहगांव चांदोन में जश्न का माहौल है। विवेक सागर के भरेपूरे परिवार के साथ ही गांव के सैकड़ों निवासी भी सुबह से ही टेलीविजन पर आंखे लगाए हुए थे। भारतीय टीम की विजय के साथ ही देश के नाम पर कांस्य पदक सुनिश्चित होते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे। परिजन और ग्रामीण ढोल बाजों की थाप पर जमकर थिरके। परिजन और विवेकसागर की मित्रमंडली की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और सब लोग मीडिया को बाइट देते रहे। गांव में मीडिया का भी जमावड़ा था। भोपाल में टीटीनगर स्टेडियम में भी खेल प्रेमियों ने भारत और जर्मनी के बीच खेला गया पूरा मैच देखा और कांस्य पदक मिलने पर सभी ने प्रसन्नता जाहिर की।

रवि ने सोना नहीं चांदी दिलाई

फाइनल में रजत पदक से करना पड़ा संतोष

टोक्यो। भारत के कुश्ती गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी महाबली सतपाल के शिष्य पहलवान रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलम्पिक के कुश्ती मुकाबलों में गुरूवार को पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में रूसी ओलम्पिक समिति के जावूर युगेव से 4-7 से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रवि ने इसके साथ ही भारत को इन खेलों का दूसरा रजत पदक और ओवरआल पांचवां पदक दिला दिया। रवि ने इस रजत के साथ ही लंदन ओलम्पिक के रजत विजेता सुशील कुमार की उपलब्धि की बराबरी कर ली लेकिन वह अभिनव बिंद्रा के 2008 ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने के प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर पाए। भारतीय पहलवान रवि ने मुकाबले में युगेव के खिलाफ सावधानी से शुरुआत की लेकिन रूसी पहलवान पहले दो अंक जुटाने में कामयाब रहे। रवि ने वापसी करते हुए दो अंक लिए और मैच में 2-2 से बराबरी कर ली। युगेव ने इसके बाद फिर दो अंक लेकर 7-4 की बढ़त बना ली।

आखिरी 10 सेकंड में फिसला ब्रॉन्ज

बढ़त बनाने के बाद हारे पहलवान दीपक पूनिया

टोक्यो । भारतीय युवा पहलवान दीपक पूनिया को तोक्यो ओलिंपिक में कुश्ती के 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने सैन मारिनो के पहलवान माइलेस नाजिम अमीन के खिलाफ शुरुआत में बढ़त भी ले ली थी, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड में अमीन ने बाजी पलटते हुए भारतीय पदक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केडी जाधव भारत को कुश्ती में पदक दिलाने वाले पहले पहलवान थे जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।

ओलिंपिक पदकधारी पर इनामों की बौछार

सरकारी नौकरी से लेकर मिला करोड़ों रुपए का प्राइज

नई दिल्ली । देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से लेकर पहलवान रवि दहिया और हॉकी टीम के खिलाड़ी एक ही दिन में करोड़पति बन गए हैं। उन खिलाड़ियों की भी झोली खाली नहीं रही, जिन्होंने ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया।

राज्य सरकारों से लेकर रेलवे, भारतीय ओलिंपिक संघ और कुछ बिजनेसमैन तक ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एक करोड़ कैश और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया है। वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे की ओर से 2 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान किया है। मणिपुर सरकार ने ओलिंपिक में भाग लेने वाले राज्य के हर खिलाड़ी को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बैंडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वालीं पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 लाख रुपए कैश देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने भी सिंधु को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय मुक्केबाज लवलिना बोरगोहेन टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। असम के गोलाघाट की रहने वाली लवलिना को असम सरकार ने जीत का बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा उनके लिए नहीं बल्कि उनके गांव के लोगों के लिए भी खुशी का सबब बन गया है। ये सड़क कई सालों से खराब थी। लवलिना की जीत ने इस सड़क को जिंदा कर दिया।

- **हॉकी टीम के प्लेयर्स को एक करोड़ से ढाई करोड़ रुपए तक का इनाम :** ओलिंपिक इतिहास में 41 साल बाद मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी प्लेयर्स भी करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पंजाब सरकार ने टीम में शामिल अपने 10 खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने भी राज्य के दो खिलाड़ियों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए, खेल विभाग में नौकरी और कंसेशनल रेट पर प्लॉट देने का ऐलान किया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने एक खिलाड़ी वरुण कुमार को 75 लाख रुपए कैश देने की घोषणा की है। ओलिंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ओडिशा सरकार ने स्पॉन्सर किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 41 साल बाद ओलिंपिक में मेडल जीतने वाली हॉकी टीम को 16 अगस्त को सम्मानित करेंगे।
- **पहलवान रवि दहिया को चार करोड़ कैश :** हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्?टर ने टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को चार करोड़ रुपए कैश के साथ क्लास वन की सरकारी नौकरी और कंसेशनल रेट पर प्लॉट देने की घोषणा की है।
- **मेडलिस्ट, कोच और खिलाड़ियों को रेलवे देगा कैश प्राइज :** रेलवे ने भी टोक्यो ओलिंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को कैश अवॉर्ड देने की घोषणा की है। रेलवे ने गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपए और उनके कोच को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और कोच को 20 लाख दिए जाएंगे। ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और कोच को 15 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा ओलिंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

भारतीय ओलिंपिक संघ भी देगा कैश प्राइज

- भारतीय ओलिंपिक संघ ने मेडल विजेताओं के लिए कैश प्राइज की घोषणा पहले से कर रखी है। इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने गोल्ड जीतने पर 75 लाख रुपए, सिल्वर जीतने पर 40 लाख और ब्रॉन्ज जीतने पर 25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

महिला हॉकी खिलाड़ियों को घर और कार देने का ऐलान

- सूरत के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया ने भी भारतीय महिला हॉकी

भारत इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से जीतेगा सीरीज

सुनील गावस्कर ने कहा

नई दिल्ली। सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम इंग्लैंड को पराजित कर सकती है। मेरा मानना है कि 4-0 होगा अगर सूरज निकला तो। अगर ओवरकास्ट रहा तो टीम 3-1 से जीतेगी। उन्होंने कहा, मेरा इंग्लैंड का पहला दौरा 50 साल पहले हुआ था और हमने वेस्टइंडीज को हाल ही में हराया था, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ था। उस मजेदार दौरे में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मेल था।

उस दौरान काउंटी टीमों के खिलाफ भी कुछ मैच थे। हमने इंग्लैंड भी घूमा और सेंट पॉल कैथेड्राल, द लंदन जू, द यूनीवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सहित अन्य जगह गए थे। एक दिन में एक पाउंड के तंग बजट होने के कारण, हम बढ़िया भोजन अनुभव का आनंद नहीं ले सके, लेकिन हमें फास्ट-फूड आउटलेट्स से संतुष्ट होना पड़ा। मौजूदा टीम भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम है। केवल 1983 से 1986 तक की टीमों में एक समान गहराई और संतुलन था। यह टीम हालांकि बेहतर है क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में उनके वातावरण में पराजित किया और उनके पास बल्ले और गेंदबाजी विभाग में कई गेम चेंजर हैं। अगर सूरज निकला तो टीम आसानी से सीरीज जीत सकती है और कुछ ओवरकास्ट दिन रहे तो भी वे जीत सकते हैं लेकिन हो सकता है एक टेस्ट में उन्हें हार मिले।

चीन की 14 साल की कुआन ने जीता गोल्ड

10 मीटर डाइविंग प्लेटफार्म स्पर्धा में

टोक्यो । चीन की 14 साल की कुआन होंगचान ने ओलिंपिक खेलों में महिलाओं की 10 मीटर डाइविंग प्लेटफार्म स्पर्धा में गुरुवार को दबदबा कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस पांच दौर की प्रतियोगिता के दूसरे और चौथे दौर में सभी सातों जजों ने उन्हें पूरे 10 अंक दिए। उन्होंने कुल 466.20 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि इसका रजत पदक चीन की ही 15 वर्षीय चेन युशी 425.40 के नाम रहा। चेन 2019 की विश्व चैंपियन है और वह इन खेलों में 10 मीटर सिंक्र टीम स्पर्धा में पहले ही स्वर्ण पदक जीत चुकी है। कुआन इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली चीन की दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं। यह रिकार्ड फुमिंगशिया के नाम है, जिन्होंने 1992 ओलिंपिक में 13 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीता था। अपना चौथा ओलिंपिक खेल रही आस्ट्रेलिया की मेलिसा वू ने 341.40 अंकों के साथ इस स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया।

विवेक सागर के गांव में जश्न का माहौल

भोपाल । टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को पराजित कर कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर के मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित गृहगांव चांदोन में जश्न का माहौल है। विवेक सागर के भरेपूरे परिवार के साथ ही गांव के सैकड़ों निवासी भी सुबह से ही टेलीविजन पर आंखे लगाए हुए थे। भारतीय टीम की विजय के साथ ही देश के नाम पर कांस्य पदक सुनिश्चित होते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे। परिजन और ग्रामीण ढोल बाजों की थाप पर जमकर थिरके। परिजन और विवेकसागर की मित्रमंडली की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और सब लोग मीडिया को बाइट देते रहे। गांव में मीडिया का भी जमावड़ा था। दरअसल टीम की उपलब्धि पर सिर्फ चांदोन या होशंगाबाद ही नहीं, पूरा प्रदेश गौरवांवित महसूस कर रहा है। भोपाल में टीटीनगर स्टेडियम में भी खेल प्रेमियों ने भारत और जर्मनी के बीच खेला गया पूरा मैच देखा और कांस्य पदक मिलने पर सभी ने प्रसन्नता जाहिर की। अब सभी लोग विवेकसागर के भोपाल वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

विनेश क्वार्टरफाइनल में हारीं

टोक्यो । विश्व नंबर एक भारतीय पहलवान विनेश फोगाट यहां गुरुवार को महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया की वेनेसा कलाडजिंस्काया से हार गईं। वेनेसा शाम को सेमीफाइनल में हार गयीं और उनकी हार के साथ विनेश की रेपेचेज में जाने की उम्मीदें समाप्त हो गयीं। बुल्गारियन पहलवान ने शुरू से ही मुकाबले में आक्रामकता दिखाई और शुरुआत में ही 2-0 की बढ़त ले ली। विनेश ने हालांकि वापसी करते हुए दो अंक लिए, लेकिन अंत में वेनेसा ने विनेश को 9-3 से पस्त करते हुए मुकाबला जीत लिया। विनेश के पास रेपचेज राउंड में पहुंचकर कांस्य पदक जीतने का मौका था, बशर्ते वेनेसा फाइनल में पहुंचे।

बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद ट्रेस्कोथिक ने माना इंग्लैंड ने ठीक से तैयारी नहीं की

नाटिंघम । जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे नाटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 183 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में खराब प्रदर्शन के लिए टीम के बल्लेबाजी कोच मार्क्स ट्रेस्कोथिक ने कम टेस्ट मैच खेलना कारण बताया है। उन्होंने यह भी माना कि टीम ने ठीक तरह से तैयारी नहीं की। मैच में इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। रूट ने 108 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से सर्वाधिक 64 रन बनाए। इंग्लैंड के चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व ओपनर ने कहा कि शेड्यूलिंग हमेशा एक मुद्दा होता है और टेस्ट सीरीज के मद्देनजर आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट खेलें। बता दें कि इंग्लैंड की टीम ... व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली। वहीं अ... घरेलू क्रिकेट की बात करें वहां टी 20 ब्लास्ट और द हंड्रेड हो रहा है यही कारण है ट्रेस्कोथिक ने शेड्यूलिं... को मुद्दा बताया। हालांकि, ट्रेस्कोथिक ने कहा कि वे इसे बहाने के तौर प... इस्तेमाल नहीं करने चाहते, बल्कि ह... उन्हें ज्यादा समय क्रीज पर देख... चाहेंगे। उन्होंने टीम के प्रदर्शन ... खराब बताया कहा कि अगली पा... और पूरी सीरीज में इंग्लैंड की टी... अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह ... कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों ... सुधार किया है। भारत 2018 ... सीरीज़ 1-4 से हार गया था, लेकि... तब से उसने ऑस्ट्रेलिया में दो सीरी... जीती हैं। ट्रेस्कोथिक ने कहा कि... पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले भारती... टीम मजबूत हुई है। हमने उ... ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां प्रदर्शन कर... करते देखा। तो यह हमारे लिए को... आश्चर्य की बात नहीं है। ...

ठोस शुरुआत के बाद लड़खड़ाया भारत

टीम इंडिया ने 125 रन पर गंवाए चार विकेट, केएल राहुल का नाबाद अर्धशतक

नॉटिंघम। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरूवार को केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक 58 रन की बदौलत चार विकेट गंवाकर 125 रन बना लिए। कम रोशनी के चलते दिन का खेल जल्द ही समाप्त कर दिया गया।

इंग्लैंड की ओर से एंडरसन ने दो विकेट लिए। एक समय भारत ने पहली पारी में ठोस शुरूआत करते हुए लंच ब्रेक तक एक विकेट पर 97 रन बना लिए थे, लेकिन लंच के बाद 28 रन जोड़कर चार महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। ... शर्मा ने 36 रन बनाए। इसके बाद टीम इंडिया ने 104 रन के स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा चार रन और विराट कोहली के विकेट गंवा दिए। दोनों विकेट जेम्स एंडरसन ने लिए। विराट कोहली बगैर खाता खोले आउट हुए। वहीं अजिंक्या ...

रूट बने इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट इतिहास रचते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 30 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी 64 रनों की पारी के बदौलत सर एलेस्टेयर कुक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के तरफ से सबसे अधिक रन बनाए थे। रूट के अब 15780 रन हो गए हैं। वह अपने करियर का 290वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। रुट 22 रन बनाते ही वह कुक के 15737 रनों से आगे निकल गए। केविन पीटरसन 13779 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान के नाम 36 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं, 105 टेस्ट ...